वर्ष: 6 अंक: 09

01-15 नवंबर, 2025 (नि:शुल्क)

न्यू इंडिया समाचार

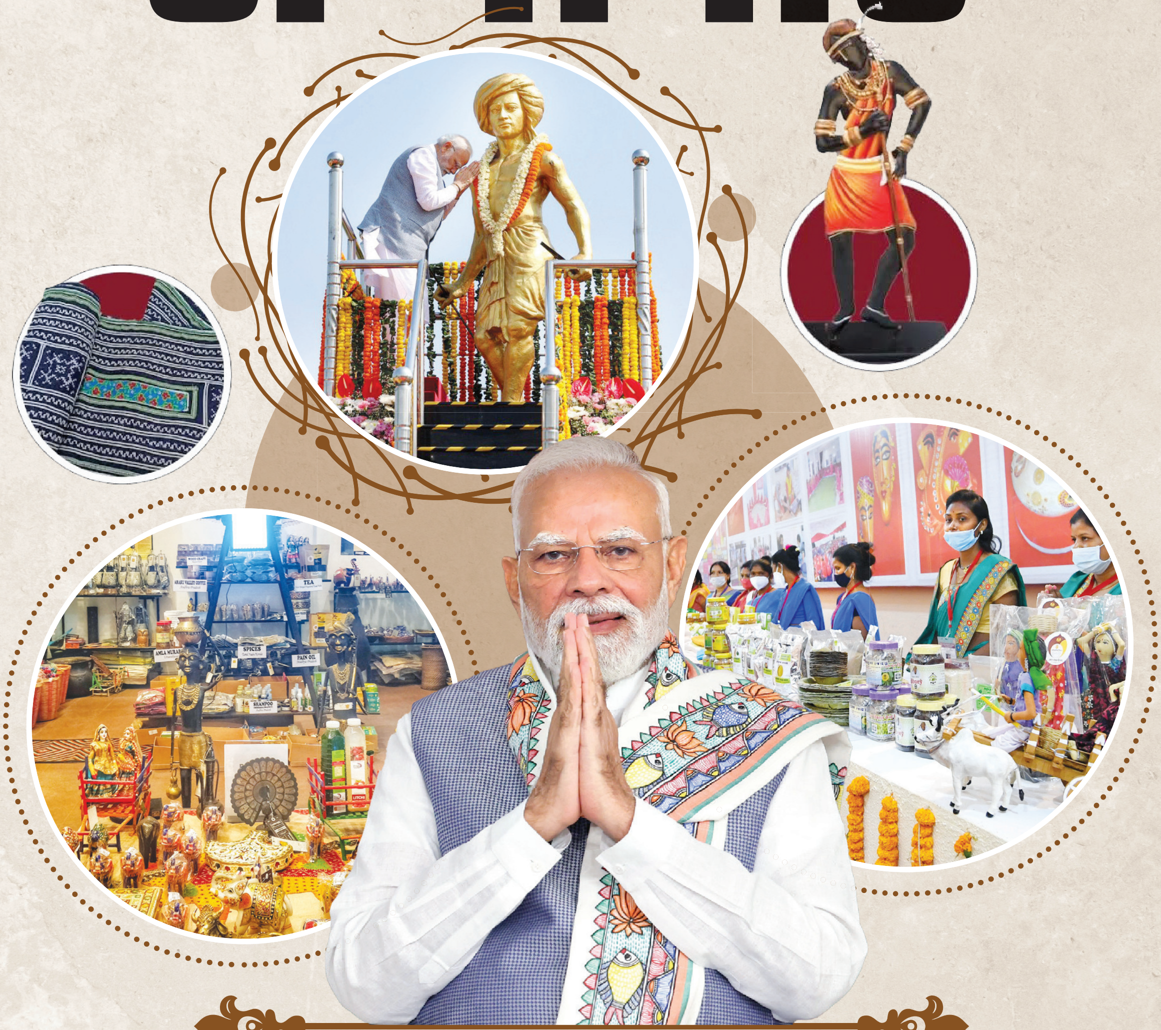

जनजातीय गौरव दिवस

आदिवासी उत्थान से राष्ट्र निर्माण तक

धरती की गहराईयों में उग रहा है विकास का कमल और आदिवासी अंचल के इसी विकास से भारत उकेर रहा है स्वर्णिम राष्ट्र का रेखाचित्र...

ई-कॉपी के लिए *QR* स्कैन करें

राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस - 9 नवंबर

कानूनी जागरूकता और न्याय तक पहुंच हो रही सुनिश्चित

समाज के कमजोर, वंचित और हाशिए पर रहे लोगों को सुलभ न्याय मिले...उन्हें नि:शुल्क कानूनी सहायता मिले, 9 नवंबर 1995 को लागू विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम इसी दिशा में एक प्रयास था। नि:शुल्क कानूनी सहायता की उपलब्धता के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से इसी दिन राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2017 में शुरु टेली लॉ और न्याय बंधु जैसे प्रयास लोगों को नि:शुल्क कानूनी सहायता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इसी दिशा में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हर नागरिक तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करने की ओर है सबसे बड़ी पहल...

कानूनी सहायता

वर्ष 2022-23 से दिसंबर 2024 तक

39.44 लाख लोगों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान की गई हैं।

- सरकार ने पांच वर्ष (2021-2026) की अवधि के लिए "भारत में न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान तैयार करना" (दिशा) नामक एक केंद्रीय क्षेत्र योजना लागू की है।
- दिशा का उद्देश्य टेली-लॉ, न्याय बंधु और कानूनी साक्षरता के माध्यम से कानूनी सेवाओं की आसान, सुलभ, सस्ती एवं नागरिक-केंद्रित डिलीवरी प्रदान करना है।
- केंद्र सरकार कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली (एलएडीसीएस) योजना लागू कर रही है जिसमें कानूनी सहायता दी जाती है। इसमें 3 वर्ष के दौरान करीब 1000 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

> जब देश का सामर्थ्य बढ़ता है तो देशवासियों को लाभ मिलता है। अंग्रेजों के जमाने से दंड संहिता में हम दबे पड़े थे। 75 साल आजादी के ऐसे ही गए, हमने दंड संहिता को खत्म कर दिया, न्याय संहिता को ले आए हैं। न्याय संहिता में भारत के नागरिक के प्रति विश्वास का भाव है। भारत के नागरिक के अंदर अपनेपन का भाव है, संवेदनशीलताओं से भरा हुआ है।
>
> – नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

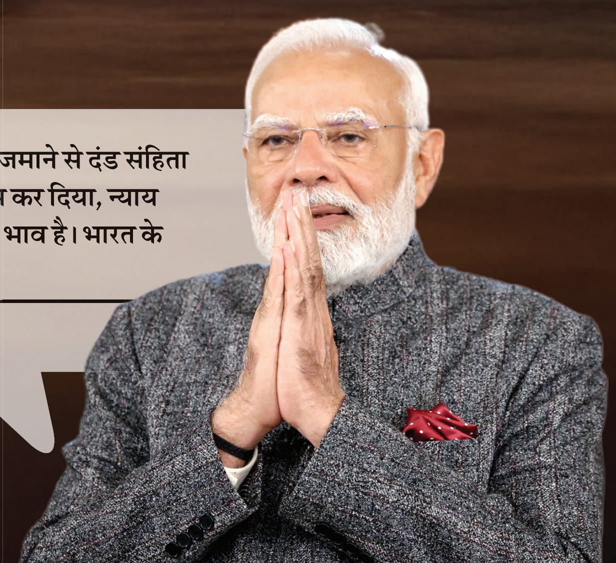

न्यू इंडिया
समाचार

वर्ष: 6, अंक: 09 | 1-15 नवंबर, 2025

प्रधान संपादक
धीरेन्द्र ओझा
प्रधान महानिदेशक
पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

मुख्य सलाहकार संपादक
संतोष कुमार

सलाहकार संपादक
विभोर शर्मा

वरिष्ठ सहायक सलाहकार संपादक
पवन कुमार

सहायक सलाहकार संपादक
अखिलेश कुमार
चन्दन कुमार चौधरी

भाषा संपादन
सुमित कुमार (अंग्रेजी)
रजनीश मिश्रा (अंग्रेजी)
नदीम अहमद (उर्दू)

चीफ डिजाइनर
श्याम तिवारी

सीनियर डिजाइनर
फूलचंद तिवारी

डिजाइनर
अभय गुप्ता
सत्यम सिंह

13 भाषाओं में उपलब्ध न्यू इंडिया समाचार को पढ़ने के लिए क्लिक करें।

https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

न्यू इंडिया समाचार के पुराने अंक पढ़ने के लिए क्लिक करें

https://newindiasamachar.pib.gov.in/archive.aspx

न्यू इंडिया समाचार के बारे में लगातार अपडेट के लिए फॉलो करें: @NISPIBIndia

अंदर के पन्नों पर...

5वां जनजातीय गौरव दिवस

जनजातीय उत्थान जहां से शुरू होता है विकास का सच

आवरण कथा

जनजातीय समुदायों को मुख्यधारा से जोड़ने की निरंतर पहल में देश ने तय किया है कि भारत की जनजातीय परंपराओं एवं शौर्य गाथाओं को अब और भी भव्य पहचान देगा। इसी सोच का परिणाम है कि बीते कुछ वर्षों में विकास का सूरज अब जंगल और पहाड़ों में बसे 11 करोड़ से अधिक जनजातीय आबादी वाले उन क्षेत्रों तक पहुंचा है जहां से शुरू होता है विकास का सच और विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि का मार्ग... | 8-24

मेड इन इंडिया

वैश्विक मंच पर भारत की मोबाइल क्रांति

इंडिया मोबाइल कांग्रेस-2025 में 150 से ज्यादा देशों ने लिया हिस्सा | 28-29

समाचार सार | 4-5

व्यक्तित्व : सितारा देवी
जिन्हें खुद टैगोर ने दी थी नृत्य साम्राज्ञी की उपाधि | 6

विश्व पटल पर गूंजा भारत का सामाजिक सुरक्षा संकल्प
भारत इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन पुरस्कार 2025 से सम्मानित | 7

गति+प्रगति = विकसित भारत
मुंबई को दूसरे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे समेत 69 हजार करोड़ रुपये की सौगात | 25-27

पीएम-सेतु : कौशल और भविष्य के अवसरों को जोड़ने वाला सेतु
भारत के युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उपहार | 30-31

600 रुपये तक बढ़ाई रबी फसलों की एमएसपी
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी | 32-33

एमएसएमई के लिए पहल... आसान हुआ उन्नति का मार्ग
पीएम मोदी की 12 घोषणाओं के 7 वर्ष पर विशेष | 34-35

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का भारत दौरा

मजबूत हो रही दो प्रमुख लोकतंत्र की साझेदारी

ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर की भारत की पहली राजकीय यात्रा | 36-37

अन्नदाता को धन धान्य व दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की सौगात

पीएम मोदी ने 41 हजार करोड़ रुपये की सौगातों के साथ शुरू की दो नई योजनाएं | 38-40

प्रकाशक और मुद्रक: कंचन प्रसाद, महानिदेशक, सीबीसी (केंद्रीय संचार ब्यूरो)। **मुद्रण:** जेके ऑफसेट ग्राफिक्स प्रा. लि., बी-278, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110020। **पत्राचार और ईमेल के लिए पता:** कमरा संख्या-1077, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली- 110003। **ईमेल-** response-nis@pib.gov.in आर. एन. आई. नंबर DELHIN/2020/78812

संपादक की कलम से...

जनजातीय सशक्तीकरण समावेशी भारत का निर्माण

सादर नमस्कार।

जनजातीय समाज को स्वाभिमान से जीवन जीने का अवसर मिले और उनकी आस्था, आत्मसम्मान व संस्कृति की रक्षा हो, आज यह केवल राज्य की प्राथमिकता नहीं, बल्कि संकल्प बन गया है। पिछले दशक के दौरान सरकार ने जनजातीय समाज के सशक्तीकरण के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं ताकि ये विकास की मुख्यधारा से जुड़कर विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभा सकें। किसी भी देश के सामान्य नागरिक का जीवन तब सुविधापूर्ण होता है, जब वह रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर निवास, भोजन, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं क्षमता विकास के अवसरों को लेकर आश्वस्त होता है, तब वह खुद आगे बढ़कर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित होता है।

जनजातीय आबादी भले ही छोटी है लेकिन यह देश भर के दूर दराज के इलाकों में फैली हुई है। केंद्र सरकार उनके विकास और कल्याण के लिए निरंतर कदम उठा रही है ताकि विकास का लाभ इन गावों, पहाड़ियों एवं जंगलों में बसे हुए प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सके। पिछले दस वर्षों में चाहे यातायात के साधन, बिजली, पानी तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी हो या लगभग 24 लाख जनजातीय परिवारों को वन अधिकार अधिनियम के तहत भूमि और आजीविका की सुरक्षा दिलाना हो, या फिर युवाओं की शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थाओं का विस्तार, एकलव्य विद्यालय जैसी विशेष व्यवस्था और प्रति वर्ष लगभग 30 लाख जनजातीय युवाओं के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था, केंद्र सरकार ने विभिन्न योजनाओं के जरिए जनजातीय विकास को नई दिशा दी है। सुदृढ़ बाजार नेटवर्क तैयार होने से आज महुआ, शहद जैसे वन्य उत्पाद तथा जनजातीय शिल्प यहां की महिलाओं की आजीविका सुनिश्चित कर रहे हैं। इन सबके परिणामस्वरूप आज हमारा जनजातीय समाज भारत की विकास यात्रा में एक सक्षम और सबल भागीदार के रूप में सक्रिय भूमिका निभा रहा है।

इस 15 नवंबर को देश 5वां जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है और भागवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का समापन भी हो रहा है। इसलिए जनजातीय विकास के लिए समर्पित केंद्र सरकार की योजनाएं और नीतियां ही इस बार हमारी आवरण कथा बनी हैं।

इसके अलावा व्यक्तित्व की कड़ी में प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना सितारा देवी, भारत को सामाजिक सुरक्षा के लिए वर्ष 2025 का आईएसएसए पुरस्कार, फ्लैगशिप के तहत 2 नवंबर, 2018 को एमएसएमई के लिए शुरू की गई 12 घोषणाओं से बीते सात वर्ष में उद्योग क्षेत्र में हुई उन्नति, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पखवाड़े भर के कार्यक्रमों को इसमें शामिल किया गया है।

साथ ही, पत्रिका के इनसाइड पेज पर राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस और बैक कवर पर आदि क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के की 179वीं जयंती पर विशेष सामग्री को समाहित किया गया है।

आप अपना सुझाव हमें भेजते रहें।

(धीरेन्द्र ओझा)

हिंदी, अंग्रेजी व अन्य 11 भाषाओं में उपलब्ध पत्रिका पढ़ें/डाउनलोड करें।
https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

आपकी बात...

सभी के लिए उपयोगी पत्रिका

न्यू इंडिया समाचार पाक्षिक पत्रिका की हार्ड कॉपी प्राप्त हुई। पत्रिका भेजने के लिए पूरी टीम को बहुत-बहुत धन्यवाद। इस पत्रिका से बहुत उपयोगी जानकारी मिल रही है। यह सभी प्रकार के लोगों जैसे छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों, गृहिणियों, आदि के लिए बहुत उपयोगी है। मुझे यह बहुत पसंद आई। अब मैं इसे हर महीने पढ़ने का प्रयास करता हूं। पत्रिका का डिजाइन बहुत बेहतरीन है।

pramilamjamdade@gmail.com

न्यू इंडिया समाचार पत्रिका : शासकीय योजनाओं की जानकारी के लिए गाइड

न्यू इंडिया समाचार 16 - 30 सितंबर 2025 का अंक पढ़ने का मौका मिला। देश में कहावत है - आयुष्मान भवः... इस संदर्भ में स्वास्थ्य ही धन है, यह संदेश मुझे बहुत पसंद आया। कुल मिलाकर पत्रिका में भारत सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं और लक्ष्यों पर पाठकों को विशेष जानकारी मिलती है। मैं इस पत्रिका का नियमित पाठक हूं क्योंकि यह विशेष रूप से छात्र समुदाय के लिए बहुत उपयोगी है।

rabisatapathy09@gmail.com

इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे पढ़कर मिली खुशी

मैं आंध्रप्रदेश मंडल में भारतीय डाक विभाग में डाकिया के पद पर कार्यरत हूं। मुझे न्यू इंडिया समाचार पत्रिका पढ़ने का बेसब्री से इंतजार रहता है। पत्रिका के एक अंक में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में जानकारी पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई। इस पत्रिका में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में जानकारी शामिल करने और इसे भारत के लोगों के और करीब लाने के लिए आपका धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के एक नागरिक के रूप में, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ओर से अपने आसपास के लोगों की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मुझे प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा के अनुसार 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने में भागीदार बनने पर भी गर्व है।

baseddula@gmail.com

भारत की प्रगति की झलक प्रस्तुत करती है पत्रिका

यह पत्रिका भारत की प्रगति की एक झलक प्रस्तुत करती है। मुझे यह पत्रिका डाक द्वारा प्राप्त होती है। इस बार मुझे अगस्त (16-31) और सितंबर (1-15) के अंक एक साथ प्राप्त हुए। यह विज्ञान, अर्थशास्त्र, अंतरराष्ट्रीय संबंध, कृषि, उद्योग, संस्कृति, प्रतिष्ठित व्यक्तियों के जीवन और कार्यों पर प्रकाश डालती है। संक्षेप में कहें तो यह पत्रिका जानकारी का एक असाधारण भंडार है। इसका आवरण और सजावट सुरुचिपूर्ण और साफ-सुथरा है। मुझे आशा है कि पत्रिका की यह विशेषता भविष्य में भी बनी रहेगी।

deshamar1976@gmail.com

पत्राचार और ईमेल के लिए पताः कमरा संख्या-1077, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली- 110003.
ईमेल- response-nis@pib.gov.in

न्यू इंडिया समाचार को आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर हर शनिवार-रविवार को दोपहर 3:10 से 3:25 बजे तक सुनने के लिए QR कोड स्कैन करें।

समाचार सार

ईपीएफ की निकासी अब और सरल व तेज... जरूरी नहीं कारण बताना

आपका पैसा कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में जमा है तो उसे निकालना अब और सरल व तेज हो गया है। अब 13 अलग-अलग श्रेणियों और अनगिनत शर्तों को सरल बनाकर एक समान प्रावधान किया गया है। इसका लाभ 30 करोड़ से अधिक लोगों को मिलेगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में यह फैसले लिए गए।

निकासी की लिमिट हुई सरल - चाहे राशि की निकासी हो या फ्रीक्वेंसी

- आंशिक निकासी के लिए अब सिर्फ 3 श्रेणी रखी गई हैं, आवश्यक जरूरतें, आवासीय और विशेष परिस्थितियां। सभी तरह की आंशिक निकासी के लिए 1 साल की समय सीमा लागू होगी।
- पहले शादी और घर निर्माण के लिए राशि निकालने हेतु 5 और 7 साल की सेवा अनिवार्य थी, अब सिर्फ एक साल।
- शिक्षा के लिए 10 बार और शादी के लिए 5 बार राशि निकाल सकेंगे। अभी तक केवल 3 बार की सुविधा थी। विशेष परिस्थिति या आपात स्थिति में साल में दो बार तक पूरी पात्र राशि बिना किसी सवाल-जवाब के निकाली जा सकेगी।
- अब कर्मचारी अंशदान, नियोक्ता अंशदान और ब्याज राशि मिलाकर 75% तक राशि निकालने की अनुमति।

अधिक कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की पहल

योग्य कर्मचारी, जिन्होंने 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच सर्विस जॉइन की है, अब नियोक्ता द्वारा मामूली पैनल डैमेज के साथ स्वेच्छा से उन्हें ईपीएफओ के अंतर्गत नामांकित किया जा सकेगा। कर्मचारी नामांकन योजना 1 नवंबर 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक लागू।

ईपीएफओ सुधार से अब कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा होगी सुनिश्चित

- नौकरी छूटने के बाद 75% तक राशि तुरंत निकाली जा सकती है। बची हुई 25% राशि 1 वर्ष पूरा होने पर।
- पहले बार-बार निकासी से सेवा में ब्रेक आ जाता था, क्योंकि पहले नौकरी छूटने पर 2 महीने बाद पूरी राशि निकालने की छूट थी। इससे पेंशन के लिए 10 साल की निरंतर सर्विस पेंशन अनिवार्यता पूरी नहीं हो पाती थी, जिससे पेंशन नहीं मिलती थी।

पेंशन सर्विस अब आपके दरवाजे पर

ईपीएफओ ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ मिलकर ईपीएफ'95 पेंशन धारकों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा को उनके घर तक निःशुल्क पहुंचाने का निर्णय लिया है।

आधार 7-15 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट निःशुल्क

आपका बच्चा 7 वर्ष से 15 वर्ष के बीच है और उसका आधार बायोमेट्रिक नहीं कराया है तो आपके लिए यह काम की खबर है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने इस आयु वर्ग के बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (एमबीयू-1) के सभी शुल्क माफ कर दिए हैं। यह छूट 1 अक्टूबर, 2025 से शुरू होकर अगले एक वर्ष तक लागू रहेगी। इस छूट से करीब 6 करोड़ बच्चों को लाभ होगा।

आधार में निःशुल्क बायोमेट्रिक अपडेट की सुविधा से बच्चों की शिक्षा, छात्रवृत्ति और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजनाओं तक पहुंच आसान होगी। नई छूट लागू होने के बाद अब एमबीयू-1 और एमबीयू-2 यानी 5-17 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए यह अपडेट प्रक्रिया निःशुल्क होगी।

AADHAAR

संचार साथी पहल

डिजिटल सिस्टम ने बरामद कराए 6 लाख से अधिक मोबाइल हैंडसेट

आपका मोबाइल खो गया है या चोरी हो गया है तो पुलिस में शिकायत या प्राथमिक सूचना दर्ज कराने के साथ ही www.sancharsaathi.gov.in पर रिपोर्ट करें। यहां रिपोर्ट किए जाने पर न सिर्फ मोबाइल को ब्लॉक कर दिया जाता है बल्कि उसे सरकार के डिजिटल सिस्टम के साथ इस तरह लिंक किया जाता है कि मोबाइल मिलने की संभावना बढ़ जाती है। मई 2023 में शुरू संचार साथी अब भारत का सबसे व्यापक डिजिटल सुरक्षा प्लेटफॉर्म बन गया है। यहां रिपोर्ट की गई मोबाइल चोरी या खो जाने की 39.56 लाख शिकायतों में से 24.46 लाख ट्रेस कर लिए गए हैं। इतना ही नहीं 6.39 लाख से अधिक हैंडसेट बरामद भी कर लिए गए हैं।

संचार साथी पर रिपोर्ट किए गए खोए या चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट को किसी भी तरह के दुरुपयोग से रोकने के लिए पूरे भारत में दूरसंचार नेटवर्क पर ब्लॉक कर दिया जाता है। जैसे ही इस मोबाइल हैंडसेट के साथ किसी सिम का उपयोग किया जाता है, स्वचालित ट्रेसेबिलिटी सक्रिय हो जाती है और नागरिकों के साथ-साथ उस संबंधित पुलिस स्टेशन को भी अलर्ट भेज दिया जाता है जहां खोए या चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट की शिकायत दर्ज की गई थी। नागरिकों को एसएमएस के माध्यम से संपर्क करने के लिए सक्रिय ट्रेसेबिलिटी में पुलिस स्टेशन का विवरण प्रदान किया जाता है।

विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीते रिकॉर्ड 22 पदक

विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रिकॉर्ड 22 पदक जीते। इसमें 6 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य पदक शामिल है। पदक तालिका में भारत ने 10वां स्थान हासिल किया। भारत ने पहली बार विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की सफल मेजबानी कर विश्व में गौरवपूर्ण स्थान हासिल किया। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के पदक विजेताओं में सरकार की टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के 15 और खेलो इंडिया कार्यक्रम का एक एथलीट शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरा एथलीटों की सराहना करते हुए कहा, "हमारे पैरा-एथलीटों द्वारा एक ऐतिहासिक प्रदर्शन! उनकी सफलता कई लोगों को प्रेरित करेगी। मुझे अपने दल के प्रत्येक सदस्य पर गर्व है। मैं उनके भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं देता हूं।"

भारत ने दुबई में 2019 में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 9 पदक, 2023 में पेरिस में 10 और 2024 में कोबे में 17 पदक जीते थे। वहीं पैरालंपिक में भारतीय एथलीटों ने 2016 में जहां सिर्फ 4 पदक जीते थे, वहीं 2024 के पेरिस पैरालंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ 29 पदक हासिल किए।

अब नए स्वरूप में दूरदर्शन पर महाभारत

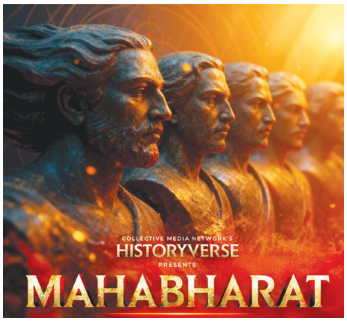

महाकाव्य महाभारत के एपिसोड नए एआई वर्जन में 2 नवंबर, 2025 से आप हर रविवार को सुबह 11 बजे राष्ट्रीय टेलीविजन नेटवर्क दूरदर्शन पर देख सकेंगे। इसके लिए प्रसार भारती और कलेक्टिव मीडिया नेटवर्क ने साझेदारी की है। यह एपिसोड भारत और दुनिया भर के डिजिटल दर्शकों के लिए वेव्स ओटीटी के माध्यम से एक साथ उपलब्ध होंगे। उन्नत एआई उपकरणों का उपयोग करते हुए, इस श्रृंखला में महाभारत महाकाव्य के व्यापक स्वरूप, उसके पात्रों, युद्धक्षेत्रों, भावनाओं और नैतिक दुविधाओं को सिनेमा के पैमाने और अद्भुत यथार्थवाद के साथ फिर से तैयार किया गया है। यह परियोजना मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया की भावना को मूर्त रूप देती है। यह आधुनिक प्रसारण में विकास और विरासत के एक साथ आने की अभिव्यक्ति है।■

...जिन्हें खुद टैगोर ने दी थी नृत्य साम्राज्ञी की उपाधि

सदियों में कभी-कभी कोई ऐसा कलाकार जन्म लेता है, जिसकी कला केवल संसार को चकाचौंध ही नहीं करती, बल्कि सांस्कृतिक विरासत की वह नींव रखती है, जिस पर आने वाली पीढ़ियां अपनी पहचान की इमारत खड़ी करती हैं। संघर्ष, साधना और त्याग की इस यात्रा में ऐसा ही एक नाम है, सितारा देवी। जिन्होंने कथक को केवल नृत्य नहीं, बल्कि जीवन का उत्सव बना दिया...और जिनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर स्वयं गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने दी थी उन्हें 'नृत्य साम्राज्ञी' की उपाधि...

जन्म : 8 नवंबर 1920, मृत्यु : 25 नवंबर 2014

तारीख-8 नवंबर 1920... स्थान-कोलकाता, दिन धनतेरस का। एक बच्ची का जन्म हुआ। कहते हैं, नवजात का मुंह कुछ टेढ़ा था। इससे भयभीत माता-पिता ने उसे एक दाई को सौंप दिया। दाई ने उसका नाम रखा धन्नो। दाई ने रात दिन मालिश कर उस बच्ची के मुंह के टेढ़ेपन को काफी हद तक दूर किया। माता-पिता को जब इसकी जानकारी मिली तो आखिर 8 वर्ष बाद वह फिर बच्ची को घर वापस ले आए। धन्नो अब धनलक्ष्मी हो चुकी थी। उस समय विवाह काफी कम उम्र में ही हो जाया करता था। लिहाजा 8 साल की उम्र में ही धनलक्ष्मी का विवाह भी करा दिया गया। ससुराल वाले चाहते थे कि धनलक्ष्मी घर के कामकाज में रुची ले लेकिन, उन्होंने स्कूल जाने की जिद ठान ली। नतीजा विवाह टूट गया। वाराणसी के रहने वाले पिता मूल रूप से कथक कलाकार थे, सो बच्ची की रगों में भी नृत्य पहले से ही बसा हुआ था। पिता सुखदेव महाराज तब तक अपनी बेटी में कुछ कर गुजरने की क्षमता जान चुके थे। उन्होंने धनलक्ष्मी की बजाय उनका नाम सितारा रख दिया। सितारा ने शंभु महाराज और पंडित बिरजू महाराज के पिता अच्छन महाराज से नृत्य की शिक्षा ग्रहण की। 10 वर्ष की उम्र होने तक वह एकल नृत्य का प्रदर्शन करने लगीं। अधिकतर वह सिनेमाहाल में फिल्म के बीच में पंद्रह मिनट के मध्यान्तर के दौरान अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया करती थीं। यह वह दौर था, जब किसी स्त्री के स्टेज पर नृत्य को ठीक निगाह से नहीं देखा जाता था। 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने पहली बार फिल्मों की दुनिया में कदम रखा। कथक से बॉलीवुड का परिचय कराने का श्रेय उन्हें ही दिया गया। उन्होंने शहर का जादू, स्वामी, रोटी और मदर इंडिया जैसी फिल्मों में काम किया। हालांकि, मदर इंडिया के बाद में उन्होंने शास्त्रीय नृत्य पर ध्यान देने के लिए फिल्मों में काम करना बंद कर दिया।

सितारा देवी से जुड़ा एक और किस्सा अक्सर याद किया जाता है। कहते हैं कि 16 वर्ष की सितारा की एक कार्यक्रम में प्रस्तुति देख रवींद्रनाथ टैगोर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सितारा देवी को 'नृत्य सम्राज्ञी' का उपनाम दे दिया। साथ ही, सराहना के तौर पर एक शॉल और 50 रुपये का उपहार भी दिया। गुरुदेव का कहा सही भी साबित हुआ। अपने प्रदर्शन से उन्होंने पूरी दुनिया का मन मोहा तो कथक को नया आयाम भी दिया। देश के हर कोने के साथ उन्होंने दुनिया के हर महत्वपूर्ण देश में शो किए, जिसमें इंग्लैंड के रॉयल अल्बर्ट हॉल और न्यूयॉर्क के कार्नेगी हॉल में उनके फुल हाउस कार्यक्रम को आज भी याद किया जाता है।

सितारा देवी को पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान सहित कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 25 नवंबर 2014 को उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया था।■

समावेशी विकास, सर्वांगीण सुरक्षा

विश्व पटल पर गूंजा भारत का सामाजिक सुरक्षा संकल्प

भारत इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन पुरस्कार 2025 से सम्मानित

किसी भी नागरिक के जीवन में तीन चीजें महत्वपूर्ण होती है- स्वावलंबन, स्वश्रेय और स्वाभिमान। ईज ऑफ लिविंग के इसी दृष्टिकोण के साथ आज भारत की प्रगति का विजन भी समावेशी है, मिशन भी समावेशी है। यही समावेशी दर्शन केंद्र सरकार की प्रत्येक नीति, प्रत्येक योजना का आधार है। जिसकी गूंज देश ही नहीं, दुनिया में भी सुनाई दे रही है। सामाजिक सुरक्षा के प्रति समर्पित भारत को वर्ष 2025 का इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन(आईएसएसए) सम्मान मिला है। यह पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'अंत्योदय' के सिद्धांत को समर्पित है, जिसका उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस पुरस्कार को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्रहण किया।

- अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा वह व्यवस्था है जो समाज द्वारा व्यक्तियों और परिवारों को स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित कराने और आय सुरक्षा की गारंटी देने के लिए प्रदान की जाती है।
- यह विशेष रूप से वृद्धावस्था, बीमारी, बेरोजगारी, दिव्यांगता, मातृत्व, कार्यस्थल पर चोट लगने या कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के समय महत्वपूर्ण हो जाती है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलनों और संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेजों में परिभाषित सामाजिक सुरक्षा को एक बुनियादी मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है।
- अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के मुताबिक भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में उल्लेखनीय वृद्धि की है। वर्ष 2015 में 19% से बढ़कर यह 2025 में 64.3% हो गया है। यानी अब 95 करोड़ भारतीयों को स्वास्थ्य बीमा, पेंशन व अन्य सुविधाएं मिल रही हैं।

सम्मान पाने वाला भारत 5वां देश

इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाला भारत दुनिया का 5वां देश है। इस पुरस्कार की शुरुआत 2013 में हुई थी। वर्ष 1927 में स्थापित आईएसएसए में 158 देशों के 330 से अधिक सदस्य संगठन शामिल हैं।

सामाजिक सुरक्षा कवरेज

एक दशक में 45% से ज्यादा वृद्धि, अब 95 करोड़ लोग दायरे में

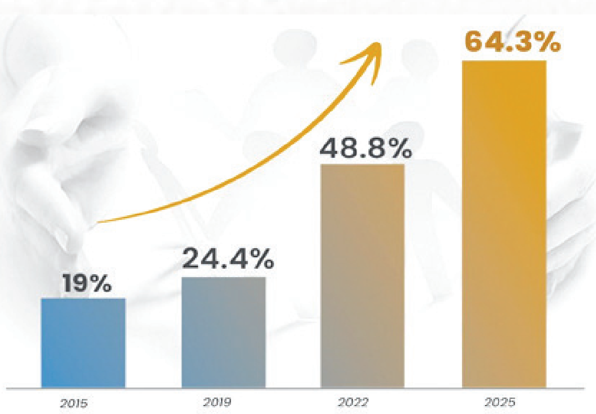

"आज भारत में ज्यादातर आबादी किसी-न-किसी सामाजिक सुरक्षा का फायदा उठा रही है और अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की बड़ी अहम रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की 64% से ज्यादा आबादी को अब कोई-न-कोई सामाजिक सुरक्षा लाभ जरूर मिल रहा है। सामाजिक सुरक्षा के मामले में यह दुनिया की सबसे बड़ी कवरेज में से एक है। आज देश के लगभग 95 करोड़ लोग किसी-न-किसी सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ पा रहे हैं, जबकि, 2015 तक 25 करोड़ से भी कम लोगों तक सरकारी योजनाएं पहुंच पाती थीं।

– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

5वां जनजातीय गौरव दिवस

जनजातीय उत्थान जहां से शुरु होता है विकास का सच

दशकों तक सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदाय के जीवन, संस्कृति और उत्पादों को नई पहचान मिल रही है। जनजातीय समुदायों को मुख्यधारा से जोड़ने की निरंतर पहल में देश ने तय किया है कि भारत की जनजातीय परंपराओं एवं शौर्य गाथाओं को अब और भी भव्य पहचान मिलेगी। इसी सोच का परिणाम है कि बीते कुछ वर्षों में विकास का सूरज अब जंगल और पहाड़ों में बसे 11 करोड़ से अधिक जनजातीय आबादी वाले उन क्षेत्रों तक पहुंचा है जहां से शुरू होता है विकास का सच और विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि का मार्ग...

इस 15 नवंबर को 5वां जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। आइए जानते हैं कि बीते 11 वर्षों में जनजातीय उत्थान की दिशा में कैसे बढ़े हैं राष्ट्र के कदम...

एक बार की बात है- सुदूर गांव में एक जनजातीय परिवार के घर अतिथि पहुंचे। उस परिवार में पति-पत्नी और एक छोटा बच्चा था, जिन्होंने अतिथि का स्वागत अत्यंत सादगी से लेकिन पूर्ण श्रद्धा से किया। अतिथि के समक्ष आधी बाजरे की रोटी और दूध से भरा एक कटोरा परोसा। यह सीमित संसाधनों के बावजूद अतिथि के प्रति असीम सम्मान का प्रतीक था। अतिथि भोजन करने लगे, तभी उनकी निगाह छोटे बच्चे पर गई जो लगातार दूध की कटोरी को निहार रहा था। अतिथि ने भांप लिया कि यह दूध बच्चे के लिए था लेकिन अतिथि के रूप में उन्हें दे दिया गया है। अतिथि ने पानी के साथ रोटी खा ली और दूध को छुआ तक नहीं। बच्चे ने जैसे ही देखा कि दूध ऐसे ही रह गया है, उसने तत्काल दूध का कटोरा उठाया और पी लिया। यह दृश्य देख अतिथि की आंखें सजल हो उठीं और मौन, मार्मिक, मर्मभेदी पल मन में उतर गया। अतिथि ने देश की अनदेखी सच्चाई-गरीबी, भूख और अभाव को अपने हृदय से महसूस किया। वह क्षण मात्र एक अनुभव नहीं था, बल्कि एक संकल्प का बीज था, एक ऐसे भारत के निर्माण का, जहां कोई बालक भूखा न हो, कोई मां अपने बच्चे की भूख से विवश न हो और हर कोई अपना जीवन गरिमा व सम्मान से जी सके। वह अतिथि कोई और नहीं, देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जो अपने शुरुआती सार्वजनिक जीवन के दिनों में पैदल, मोटरसाइकिल आदि से दूरस्थ, दुर्गम व आदिवासी अंचलों को समझने के लिए निकल पड़ते थे। इन्हीं यात्राओं ने उनके विचारों को मानवीय गहराई और आदिवासी समाज के समावेशी विकास के लिए समर्पण की प्रेरणा दी।

इसी तरह का एक और वाकया है वर्ष 1980 का। अहमदाबाद की धरा पर एक नवप्रभात उग रहा था- वनवासी कल्याण आश्रम की आधारशिला रखी जा रही थी। यह आश्रम केवल ईंट-पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि जनजातीय समाज के उत्थान का एक दिव्य संकल्प था। इसके लिए फंड की जरूरत थी। इस पावन उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक आयोजन किया गया, जिसमें नगर के प्रमुख उद्योगपति, व्यापारी और समाजसेवी आमंत्रित थे। इस सभा में एक ओजस्वी युवा नरेंद्र मोदी ने मंच संभाला। तब उनके पास न कोई बड़ा ओहदा, न कोई राजनैतिक छवि, केवल आत्मबल, सेवा का संकल्प और विद्या की अग्नि थी। उन्होंने लगातार 90 मिनट तक जनजातीय जीवन की पीड़ा, उनकी संस्कृति, संघर्ष और उपेक्षा की कथा इस प्रकार कही मानो वे स्वयं उन जंगलों में जन्मे हों। परंतु यह सहानुभूति केवल भावुकता नहीं थी, बल्कि संवेदना थी। क्या आप जानते हैं, इस भाषण की गहराई और मार्मिकता का राज क्या था? इस आयोजन में मंच संभालने के लिए उन्होंने केवल 12 दिनों में 50 से अधिक ग्रंथों का अध्ययन कर आदिवासी समाज के जीवन, समस्याओं, इतिहास से जुड़ी जानकारी हासिल की।

उस भाषण का असर हुआ कि सभा में उपस्थित व्यवसायियों की आंखों में नमी थी। एक विचलित कर देने वाली सच्चाई को उन्होंने पहली बार इतने करीब से महसूस किया था और फिर जो हुआ वह चमत्कार ही था। लोगों ने नरेंद्र मोदी के हाथ खाली चेक थमा दिए और कहा कि राशि नहीं बताएंगे, जहां जितना उचित समझें, खर्च करें। उस दिन केवल चंदा एकत्र नहीं हुआ, एक आंदोलन ने आकार लिया।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हैंडल @modiarchive पर ऐसी ही भावुक कर देने वाली कहानियां इस जनजातीय गौरव दिवस पर समीचीन होगा, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन-मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ी है और जनजातीय कल्याण का नया सूत्रपात किया है।

दरअसल, किसी भी राष्ट्र का विकास देखना हो तो उसके सुदूर अंचल की ओर देखना चाहिए। इसी दृष्टिकोण से आज का भारत आदिवासी अंचल के विकास में ही अपना भविष्य देख रहा है। धरती के सबसे करीब इन क्षेत्रों के विकास में ही भारत की अनुपम तस्वीर छुपी है, जहां पत्तों की सरसराहट में सपनों के सुर छिपे हैं और उन

"

भगवान बिरसा मुंडा ने सिखाया कि हमें कैसे अपने परिवेश और सद्भाव की भावना के साथ रहना है। अपनी संस्कृति पर गर्व करना है। उनसे प्रेरित होकर, हम उनके सपनों को पूरा करने और आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए काम कर रहे हैं।

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

सपनों को साकार करने के लिए बीते 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने अभूतपूर्व काम किए हैं।

स्वाधीनता के कई दशकों के बाद भी जनजातीय समुदाय के अधिकांश लोगों को अपना घर न होने तथा बिजली-पानी-सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में कठिन जीवन बिताना पड़ता था। बीमारी की हालत में इलाज के खर्च का बोझ उनके जीवन को और कठिन कर देता था। उनके लिए विकास के रास्ते भी सुगम नहीं थे। जनजातीय समाज के लोग अपनी सदियों पुरानी कला विरासत के बल पर बहुत सुंदर वस्तुएं बनाते हैं लेकिन कुछ ऐसे कानून थे जिससे उन लोगों के कुछ उद्यमों पर रोक लग गई थी। साथ ही, अपने उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने की जानकारी और सुविधाओं की कमी उनके विकास में बाधक थी। इस प्रकार, आवास, यातायात, चिकित्सा, शिक्षा तथा रोजगार की आवश्यकताएं पूरी न होने के कारण वे लोग विकास की मुख्यधारा से दूर रह गए थे लेकिन, अब इन सुविधाओं को उन तक पहुंचाया जा रहा है। उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। साथ ही, उनके लिए आर्थिक विकास के अवसर भी बढ़ रहे हैं। वर्तमान सरकार ने जनजातीय विकास और कल्याण की यात्रा को तेज गति से बहुत आगे बढ़ाया है। बड़े पैमाने पर अनेक अभियान और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विकास और कल्याण के सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों में जनजातीय समाज तक सभी सुविधाएं पहुंचाने के विशेष उपाय किए गए हैं।

कानूनी संरक्षण और बढ़े अधिकारों से मजबूती

"जब जनजातीय समाज प्रगति करेगा, तभी हमारा देश भी सच्चे अर्थों में प्रगति करेगा।"

समृद्ध विरासत के बावजूद लंबे समय तक हाशिए पर रहे जनजातीय समुदाय को केंद्र सरकार अपने इसी विजन के साथ देश की मुख्यधारा से जोड़ने का काम कर रही है। कानूनी संरक्षण से लेकर अधिकारों तक केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता ने जनजातीय समुदाय के बहुआयामी विकास को दी है नई दिशा...

- संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत 730 से अधिक अनुसूचित जनजातियां अधिसूचित हैं।
- 117 समुदायों को 2014-2024 के बीच अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया जबकि पिछले दशक में केवल 12 ही शामिल की गई थीं।
- 10 गुना से अधिक समुदायों के अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल होने से हाशिए पर पड़े इन समुदायों के लिए कल्याणकारी लाभ के दरवाजे खुले। शिक्षा-नौकरी में आरक्षण से लेकर राजनीतिक प्रतिनिधित्व और कानूनी सुरक्षा बढ़ी है।
- वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), वन भूमि और संसाधनों पर व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों को कानूनी मान्यता देकर आदिवासी और वन में रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाता है।

1,70,000 गांव, भारत में वन क्षेत्रों के निकट हैं। इन्हें वन सीमांत गांव कहा जाता है। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार करीब 30 करोड़ लोग देश में वनों पर निर्भर हैं।

सशक्त जनजाति, राष्ट्र का सशक्तीकरण

सशक्त जनजाति से राष्ट्र का सशक्तीकरण आज यथार्थ बन गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में लगभग 9 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति (एसटी) की है यानी संख्या में लगभग 11 करोड़ हैं। संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत देश में अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों की संख्या 730 से अधिक

सामाजिक सशक्तीकरण की दिशा में उठाए कई महत्वपूर्ण कदम

आदिवासी समुदाय और उनमें भी पिछड़े समुदायों (पीवीटीजी) के सामाजिक-आर्थिक विकास पर केंद्र सरकार लगातार ध्यान देने के साथ ही इन समुदायों को सशक्त बनाने के लिए कदम उठा रही है, ताकि आदिवासी समुदाय खुद के साथ राष्ट्र के विकास में भी दे सके योगदान...

- संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को बढ़ाने और जनजातीय लोगों के कल्याण को ध्यान में रखकर अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, आजीविका, पेयजल, स्वच्छता आदि क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की गतिविधियों में अंतर को पाटने के लिए 100% अनुदान जारी किए जाते हैं।
- 2 लाख रुपये तक रियायती लोन आदिवासी महिला सशक्तीकरण योजना में आदिवासी महिलाओं को केवल 4% ब्याज पर दिया जाता है। माइक्रो क्रेडिट योजना में 5 लाख रुपये तक के लोन आदिवासी स्वयं सहायता समूहों को दिए जाते हैं।
- प्रधानमंत्री वनबंधु कल्याण अंब्रेला योजना: देश के सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी और जनजातीय समुदाय के सामाजिक, आर्थिक स्तर को बढ़ाने के लिए 28 अक्टूबर 2014 को औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री वनबंधु कल्याण योजना की शुरुआत हुई।
- अब यह अम्ब्रेला योजना बनी है जिसमें जनजातीय समुदाय के विकास और कल्याण के लिए 6 योजनाएं शामिल की गईं हैं।

26,135 करोड़ रु. इस योजना में 2021-22 से 2025-26 तक खर्च किए जा रहे हैं।

- आदिवासी-जनजातीय क्षेत्रों में एक दशक में बढ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर

1.5 करोड़ शौचालयों का निर्माण

2.55 लाख आंगनबाड़ी शुरू की गईं

- वन अधिकार अधिनियम के तहत 25.11 लाख से अधिक जनजातीय परिवारों को अगस्त 2025 तक मान्यता मिली।

23.89 लाख व्यक्तियों को अधिकार पत्र वितरित किए गए

1.21 लाख समुदायों को अधिकार पत्र वितरित किए गए

50.75 लाख एकड़ भूभाग व्यक्तिगत अधिकारों के तहत मौजूद

181.98 लाख एकड़ भूभाग सामुदायिक अधिकारों के तहत मौजूद

- भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों में संशोधन कर गैर वन क्षेत्रों में बांस की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए बांस को पेड़ की श्रेणी से हटाया गया। इसका सीधा लाभ आदिवासी समुदाय को मिल रहा है।
- संविधान की अनुसूची V के पैरा 5.2 का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्र में किसी जनजातीय व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना है।

है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' की सोच को ध्यान में रखते हुए वर्तमान केंद्र सरकार ने समाज के सभी वर्गों के समान विकास पर निरंतर काम शुरू किया। इस विकास में केंद्र सरकार ने जनजातियों के विकास, उनकी विरासत और संस्कृति के संरक्षण को भी प्राथमिकता दी है। अधिक प्रतिबद्धता के साथ उन्हें नए प्रगति पथ के लिए सक्षम बनाया है। दरअसल, इस समुदाय ने जंगल, मरूभूमि और पहाड़ों के बीच रहकर भारत की आजादी की अलख जगाई। भारत की समृद्धि को उन्होंने अपना जीवन मंत्र बनाया। आजादी के बाद से लंबे समय तक विकास की पहुंच से दूर रहे जनजातियों के विकास, उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक स्वायत्तता की सुरक्षा के लिए देश का मौजूदा नेतृत्व बीते कुछ वर्षों से निरंतर प्रयासरत है। जनजातीय विकास के

योजनाओं से युगांतरकारी परिवर्तन

जनजातीय समुदाय को लेकर बदलाव सिर्फ सोच में नहीं आया, बल्कि उन योजनाओं के रूप में धरातल पर भी उतरा है, जिनके साथ जनजातीय समुदाय अब विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। पीएम जुगा, पीएम-जनमन और वन धन जैसी योजनाएं यह सुनिश्चित कर रही हैं कि जनजातीय नागरिकों को मिले उनका अधिकार, अवसर और सम्मान...

200 फीसदी से अधिक बढ़ाया गया जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट...

2013-14: 4,296 करोड़ रुपये

2025-26: 14,926 करोड़ रुपये

प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना

- इसके तहत 36,428 गांव की पहचान बुनियादी सुविधाएं देने के लिए की गई, जहां 50% जनजातीय आबादी और 500 अनुसूचित जनजातीय आबादी हो। इसमें नीति आयोग की तरफ से चिन्हित आकांक्षी जिलों के गांव भी शामिल हैं। प्रत्येक गांव को 20.38 लाख रुपये स्वीकृत कार्यों के लिए दिए जा रहे हैं।

15,989 गांव को मिली ग्राम विकास कार्यक्रम के लिए मंजूरी, 2,283 करोड़ रुपये जारी।

जनजातीय विकास को विस्तार

2013-14: 24,594 करोड़ रुपये

2025-26: 1,27,434 करोड़ रुपये

5 गुना से ज्यादा बढ़ा बजट

1,04,436 करोड़ रुपये वित्त वर्ष 2024-25 में जारी किए गए।

- केंद्र सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए एक कार्यनीति के रूप में 'अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (DAPST)' को लागू कर रही है।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय के अलावा 41 मंत्रालय और विभाग के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, आवास, विद्युतीकरण, रोजगार सृजन, कौशल विकास पर अपने बजट का (4.3 फीसदी से 17.5 फीसदी) निर्धारित प्रतिशत जनजातीय विकास परियोजनाओं के लिए आवंटित करना अनिवार्य है।
- DAPST के तहत 2025-26 में ये 41 मंत्रालय व विभाग 204 योजना और कार्यक्रम चला रहे हैं।
- चालू वित्त वर्ष में 1,27,434 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई। इनमें से 52 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि इन योजना और कार्यक्रम के लिए जारी भी की जा चुकी है।

वार्षिक बजट में तीन गुना बढ़ोतरी हुई है। अब देशभर में खुले एकलव्य मॉडल स्कूलों में एकलव्यों की प्रतिभा को पूरा सम्मान मिल रहा है। वन धन योजना ने आदिवासियों का जीवन बदला है तो जंगल की संपदा सशक्तीकरण का साधन बनी है। जनजातीय बच्चों के स्कॉलरशिप बजट में बढ़ोतरी हुई तो पढ़ाई से लेकर खेल के मैदान तक जनजातीय समूह के बच्चों का परचम लहरा रहा है। बोडो, ब्रू, कार्बी के साथ अब हर जनजाति में नया विश्वास जागा है। इतना ही नहीं, महानगरों से निकलकर पद्म सम्मान अब जंगल, मरूभूमि और पहाड़ों तक पहुंचा है, जिससे जनजातियों के कामों को नई पहचान मिली है।

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो इस समाज की आशाओं-आकांक्षाओं को समझने का गंभीर प्रयास हुआ। जनजातीय समाज के उत्थान एवं समृद्धि के लिए 1999 में एक अलग मंत्रालय बनाने के साथ ही 89वें संविधान संशोधन के जरिये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कर इनके हितों को सुनिश्चित करने की पहल की गई। जनजातीय समाज के उत्थान एवं सम्मान की जो शुरुआत हुई, पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

पीएम जुगा... गांव-गांव आदिवासियों का जीवन बदलने का अभियान

- 2 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के हजारीबाग से प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (पीएम जुगा) की शुरुआत की। यह धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के नाम से लोकप्रिय है। केंद्र सरकार के 17 मंत्रालय और विभाग मिलकर 31 मार्च, 2029 तक जनजातीय ग्राम उत्थान के लिए कर रहे हैं 25 उपाय।
- 79,156 करोड़ रुपये से अधिक के खर्च से इस कार्यक्रम में करीब 63,843 आदिवासी/जनजाति बहुल गांवों में सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका विकास का रास्ता आसान किया जा रहा है।
- 5.38 करोड़ से अधिक आदिवासी लोग हो रहे हैं लाभांवित, 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों के 2,911 ब्लॉक में पीएम जुगा के अंतर्गत सतत विकास के 2030 के एजेंडे के अनुरूप काम किए जा रहे हैं।

पीएम जनमन... बदल रही तस्वीर

आजादी के दशकों बाद तक 75 जनजातियां ऐसी थीं, जो आदिवासियों में भी बेहद पिछड़ी हुई थीं। इन्हीं विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के लिए 15 नवंबर, 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने खूंटी से पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) की शुरुआत की।

- पीएम जनमन का उद्देश्य 3 वर्षों में 9 मंत्रालय द्वारा मिलकर 11 उपायों के माध्यम से आर्थिक-सामाजिक तस्वीर बदलना है। कुल 24,104 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ हर मंत्रालय को निर्धारित उपाय को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई।
- ये पीवीजीटी समुदाय सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्रों में काफी पिछड़े हैं। लगभग 22 हजार बस्तियों में रहने वाले इन लोगों की आबादी करीब 28 लाख है।

इन सुविधाओं को मिली स्वीकृत

काम	स्वीकृत
मकान	4,62,159
संपर्क सड़कें(किमी)	6506
पाइप से जलापूर्ति(गांव)	18,385
सचल चिकित्सा इकाई	694
आंगनबाड़ी	2500
छात्रावास	492
घरों का विद्युतीकरण	1,43,194
नई सौर ऊर्जा योजना	9961 घर
मोबाइल टावर(बस्ती)	3894
बहुउद्देश्यीय केंद्र	1000
वन धन विकास केंद्र	516

(आंकड़े 30 जून 2025 तक)

18 अगस्त, 2025 तक किए गए कार्य

5 लाख के लगभग पक्के घर पूरे

12 हजार घर में बिजली पहुंची

692 छात्रावास स्वीकृत

282 आंगनबाड़ी केंद्र चालू

26,607 गांव में पाइप से जलापूर्ति

2,212 गांव में मोबाइल कनेक्टिविटी

5,876 परियोजनाएं मंजूर की गईं आश्रम स्कूल, सरकारी या आदिवासी रिहायशी स्कूल को अपग्रेड करने के लिए

ने उसे और सशक्त ढंग से आगे बढ़ाया है। शिक्षा किसी भी समाज के विकास की महत्वपूर्ण कड़ी है इसलिए केंद्र सरकार ने एकलव्य मॉडल स्कूल को सशक्त किया है। जनजातीय समाज के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के साथ उनकी सांस्कृतिक विरासत को सम्मानपूर्वक देश के समक्ष लाने का कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में निरंतर जारी है। जनजातीय कला, साहित्य, परंपरागत ज्ञान एवं कौशल जैसे जनजातीय विषयों को अध्ययन-अध्यापन में सम्मिलित किया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जनजातीय नायक-नायिकाओं की वीरगाथाओं को सामने लाने के उद्देश्य से देश भर में कई कार्यक्रमों के आयोजन हुए।

जनजातीय उत्थान बना जन आंदोलन

देश के लगभग 750 जनजातीय समूहों के लोग विशेष स्थान रखते हैं। इनमें पीवीटीजी समूहों की संख्या 75 है। वह देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहते हैं। आज जनजातीय समाज के लोग केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होकर आर्थिक आत्म-निर्भरता प्राप्त कर रहे हैं। उनके लिए

आदिवासी आरोग्य सरकार की प्राथमिकता

आयुष्मान भारत ने जनजातीय समुदाय के लोगों की इलाज की चिंता दूर की है तो सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारियों को खत्म करने के लिए मिशन मोड पर हो रहा है काम...

- भारत सरकार ने जनजातीय आबादी में स्वास्थ्य संबंधी असमानताओं को दूर करने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत 2023 में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की।
- 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल से पीएम मोदी ने मिशन की शुरुआत की, वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य।

7 करोड़ व्यक्तियों की स्क्रीनिंग करने का लक्ष्य, जनजातीय बहुल क्षेत्रों में 0 से 40 वर्ष की आयु के लोगों को किया गया है शामिल।

6 करोड़ लोगों की सिकल सेल रोग की जांच जुलाई माह तक की जा चुकी है। 2.15 लाख लोगों में इस रोग की पहचान के बाद निदान किया गया।

जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में एसएचसी, पीएचसी और सीएचसी स्थापित करने के लिए जनसंख्या मानदंडों को क्रमशः 5 हजार, 30 हजार और 1.20 लाख से घटाकर 3 हजार, 20 हजार और 80 हजार कर दिया गया है।

1,498 मोबाइल मेडिकल यूनिट एनएचएम के अंतर्गत दूरदराज और जनजातीय इलाकों में संचालित हैं। इनमें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों वाले क्षेत्रों में 694 यूनिट शामिल हैं।

शिक्षा से सशक्तीकरण
आदिवासी समाज की नई राह

जनजातीय आबादी की शिक्षा को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई प्रभावी कदम उठाए हैं। इन पहलों ने न सिर्फ बच्चों को स्कूल तक पहुंचाया, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से उनके जीवन स्तर में आ रहा सुधार...

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)

आदिवासी बच्चों को उनके परिवेश में नवोदय विद्यालय के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2018-19 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की शुरुआत की।

- **722** एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की स्वीकृत संख्या है देश में। हालांकि, सरकार वर्ष 2026 तक इसकी संख्या **740** करने जा रही है। जुलाई 2025 तक देश में **485** स्कूलों में पढ़ाई शुरू कर दी गई है। इससे देश भर के लगभग 3.5 लाख अनुसूचित जनजाति के छात्रों को लाभ मिलेगा।
- राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा सोसाइटी (नेस्ट्स) ने संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) इंडिया के साथ साझेदारी में राष्ट्रीय कार्यक्रम तलाश (आदिवासी योग्यता, जीवन कौशल और आत्म-सम्मान केंद्र) शुरू किया है। इसका उद्देश्य देशभर में आदिवासी छात्रों की शिक्षा और व्यक्तित्व विकास में सुधार लाना है।

विकास के अवसर बढ़ रहे हैं। प्रमुख राष्ट्रीय योजनाओं के लाभ सभी जनजातीय लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचें, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। वर्ष 2023 में 'जनजातीय गौरव दिवस' के दिन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू पीएम-जनमन अभियान का उद्देश्य देश के पीवीटीजी समुदायों के लोगों का व्यापक विकास करना है। इस अभियान के तहत 24 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत से, तीन वर्ष की समय सीमा के पहले ही, अनेक सुविधाओं को इस समुदाय के लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2024 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के दिन 2 अक्टूबर को, भगवान बिरसा मुंडा की धरती से ही केंद्र सरकार द्वारा 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' का आरंभ किया गया। लगभग 80 हजार करोड़ रुपये की लागत वाले इस अभियान का लक्ष्य है कि हर जनजातीय व्यक्ति को सरकार की

- **अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप एवं छात्रवृत्ति :** इस योजना का उद्देश्य मेधावी अनुसूचित जनजाति के छात्रों को चिन्हित कर देश भर के 265 उत्कृष्ट संस्थानों में अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करना है। इसमें आईआईटी, एम्स, आईआईएम और एनआईआईटी जैसे संस्थान शामिल हैं। विद्यार्थी के माता-पिता की आय सभी स्रोतों से 6 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

मजबूत हुआ छात्रवृत्ति इकोसिस्टम

पांच केंद्रीय छात्रवृत्ति योजनाओं से सालाना लाभ

छात्रवृत्ति योजना का बजट

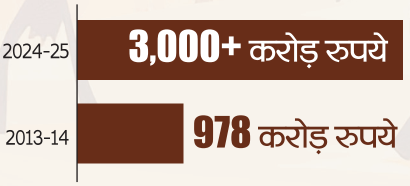

अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति

कक्षा 9 और 10 में पढ़ने वाले वैसे छात्र जिनके माता-पिता की सभी स्रोतों से आय 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक न हो। यह सुविधा मैट्रिक या उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी उपलब्ध है।

अनुसूचित जनजाति का सकल नामांकन अनुपात

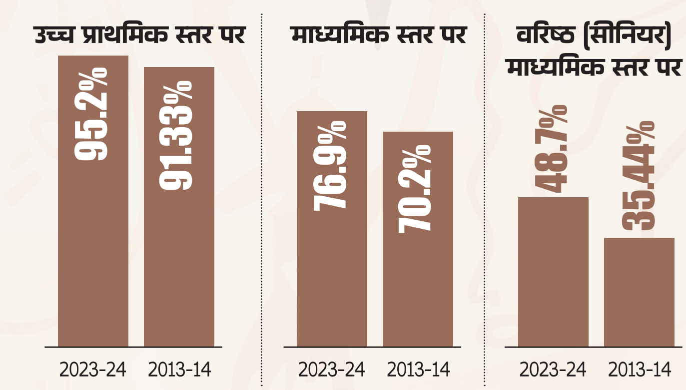

- अजजा के लिए उच्चतर शिक्षा हेतु जीईआर 2013-14 में 11.3% से बढ़कर 2021-22 में 21.2% हो गया है।
- 650 से अधिक अनुसूचित जनजाति (एसटी) की महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सदस्यों को वित्तीय साक्षरता, डिजिटल वित्त और सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए प्रशिक्षित किया गया।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय ने फेसबुक के साथ साझेदारी में पूरे भारत में जनजातीय युवाओं के डिजिटल कौशल विकास के लिए 'गोल' कार्यक्रम शुरू किया।
- राष्ट्रीय जनजातीय विद्यार्थी शिक्षा समिति और टाटा मोटर्स लिमिटेड ने जनजातीय युवाओं को कौशल-आधारित शिक्षा और रोजगार के अवसरों से सशक्त बनाने के लिए समझौता किया।

- **अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्तियां :** चयनित छात्रों को विदेश में स्नातकोत्तर, पीएचडी और पोस्ट-डॉक्टरल अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। माता-पिता की सभी स्रोतों से आय 6 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

योजनाओं का लाभ पहुंचे। सड़कों और मोबाइल कनेक्टिविटी के द्वारा हर जनजातीय गांव जुड़ सके, सभी जनजातीय परिवारों के पास अपना पक्का घर हो। विकास और कल्याण के इस अभियान से लगभग 63 हजार जनजातीय गांव लाभान्वित होंगे। इस देशव्यापी अभियान से 5 करोड़ से भी अधिक जनजातीय लोगों को लाभ पहुंच रहा है।

जनजातीय गौरव तथा संविधान के आदर्शों के प्रति देश में आज नई चेतना का संचार हो रहा है। यही भावना जनजातीय समाज सहित पूरे देश के उज्ज्वल भविष्य का आधार बन रही है। वर्ष 2023 में 'जनजातीय गौरव दिवस' के अवसर पर, प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू जाकर आशीर्वाद लिया। किसी प्रधानमंत्री द्वारा उलिहातू की यह पहली यात्रा थी। उसी दिन, झारखंड से ही 'पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महा-अभियान'

यानी पीएम-जनमन की शुरुआत हुई।

आज जनजातीय बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए देश में 700 से अधिक एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं। लगभग 30 लाख से अधिक जनजातीय छात्रों को छात्रवृत्ति मिल रही है। विदेशों में भी पढ़ने के लिए सहायता दी जा रही है। इसी का परिणाम है कि जनजातीय समाज के युवा प्रशासनिक सेवा, मेडिकल, इंजीनियरिंग व अन्य क्षेत्रों में बढ़-चढ़कर शामिल हो रहे हैं। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य के तहत जनजातीय समाज से सिकल सेल एनीमिया बीमारी के उन्मूलन का लक्ष्य भी रखा गया है। अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) के लिए पिछले दशक के दौरान कई गुना वजट में वृद्धि की गई है। वर्ष 2025-26 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट 14 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा किया गया है। जनजातीय समाज के लोगों की तेज गति से प्रगति हो यह आज राष्ट्रीय प्राथमिकता है। इसमें भी यह सोच है कि जनजातीय समाज की सदियों पुरानी पहचान बनी रहे और साथ ही उनका आधुनिक विकास भी होता रहे।

बीते कुछ वर्षों में भारत में कई नई परंपराओं का उदय हुआ है और उसी उदीयमान परंपराओं का परिणाम है कि जनजातीय समाज की प्रतिभाओं को अधिक मान्यता भी मिल रही है। जनजातीय समुदाय के 100 से अधिक लोगों को बीते 11 वर्षों के दौरान पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। अनेक राज्यों के राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री, केंद्र एवं राज्य सरकारों के मंत्रीगण तथा उच्च पदों पर आसीन अनेक व्यक्ति जनजातीय समाज से आते हैं। जनजातीय समाज के लिए, जनजातीय युवाओं के लिए आज विकास का खुला आसमान उपलब्ध है। वह जितनी भी ऊंची उड़ान भरना चाहें, समाज और सरकार उनके साथ है।

नए भारत का प्रतिबिंब बनीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु

पहली आदिवासी राष्ट्रपति और ओडिशा के आदिवासी इलाके से आने वाली पहली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का जीवन नए भारत का प्रतिबिंब है। सुदूर वन क्षेत्र से रायसीना हिल तक पहुंचने वालीं राष्ट्रपति मुर्मु उस नए भारत का भी प्रतीक बनीं हैं, जिसे अमृत काल में साकार करने के लिए देश का जन-जन जुटा है। कई दशक बाद गरीब आदिवासी परिवार की बेटी द्रौपदी मुर्मु देश की राष्ट्रपति बनी हैं, जिन्होंने आदिवासियों में भी अति पिछड़े आदिवासी समाज का विषय उठाया था। उनकी प्रेरणा से ही केंद्र सरकार ने पीएम जनमन योजना की शुरुआत की है। इसके तहत आदिवासियों में भी अति पिछड़े समाज को प्राथमिकता दी जा रही है। वनवासियों और अनुसूचित जनजातियों के वन अधिकारों को भी मान्यता दी गई है। वन संसाधन जनजातीय समाज की प्रगति का जरिया बने, इसके लिए केंद्र सरकार ने वनधन योजना शुरू की। वन उपज की चीजों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया गया। जनजातीय समाज के उत्पादों को बाजार से जोड़ा गया। इसका परिणाम है, आज देश में वन उपज में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज हो रही है। जनजातीय समाज को स्वाभिमान से जीवन जीने का अवसर मिले, यह केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता है तो

जनजातीय क्षेत्रों में अन्नदाता को सम्मान

वर्ष 2014 के बाद केंद्र सरकार ने देश के अन्नदाता को केंद्र में रख कई विकास योजनाओं की शुरुआत की। वहीं, जनजातीय इलाकों में खेती के पुराने तौर-तरीकों में बदलाव के साथ-साथ एमएसपी का विस्तार और बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण जैसे कदमों ने किया कृषि की सूरत बदलने का काम...

- 1 करोड़ से अधिक जनजातीय समुदाय के किसानों को अब तक पीएम किसान सम्मान निधि के तहत सहायता दी गई है।
- लघु वन उपज (**MFP**) के लिए पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य (**MSP**) का विस्तार कर 77 नए लघु वन उत्पादों को जोड़ा गया। पहले यह संख्या 12 थी, अब 87 उत्पाद इसमें शामिल हैं।
- जनजातीय संग्राहकों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति और आय सुरक्षा सुनिश्चित की गई।
- बुनियादी ढांचे और बाजार संपर्कों को मजबूत करने की दिशा में 1,316 हाट बाजार, 603 भंडारण इकाइयां और 22 प्रसंस्करण इकाइयां स्वीकृत की गईं। जनजातीय उत्पादों और कारीगरों के लिए सीधे बाजार तक पहुंच को सुविधाजनक बनाया गया।
- वर्ष 2015-16 में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत आदिवासी क्षेत्रों, द्वीपों और पहाड़ी क्षेत्रों सहित पारंपरिक रूप से जैविक क्षेत्रों को प्रमाणित करने के लिए बड़े क्षेत्र प्रमाणन (एलएसी) कार्यक्रम को शामिल किया गया।
- राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत जनजातीय क्षेत्रों में पशुपालन को बढ़ावा देकर स्थायी आजीविका बढ़ाने के लिए 8,500 व्यक्तिगत और समूह लाभार्थियों के लिए सहायता दी गई है।

पीएम मत्स्य संपदा योजना में रखा खास ध्यान

1 लाख व्यक्तिगत लाभार्थी और 10,000 जनजातीय सामुदायिक समूहों को अब तक दी गई सहायता।

उद्यमिता से आत्मनिर्भरता की ओर...

जनजातीय समुदाय में उद्यमिता को बढ़ावा देने और आजीविका सृजन के लिए केंद्र सरकार संकल्पित है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में ऐसे कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिन्होंने आदिवासियों को सशक्त बनाने के साथ परिवर्तनकारी सुधार की रखी है मजबूत नींव...

- ट्राइफेड द्वारा प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) के तहत 12 लाख से अधिक लाभार्थियों को जोड़ते हुए 4,661 वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) स्वीकृत किए गए। इसके साथ ही अब आदिवासी उत्पाद वैश्विक और राष्ट्रीय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं।
- ट्राइफेड के तहत 2.2 लाख से अधिक कला से जुड़े परिवार और 1 लाख से अधिक उत्पाद रजिस्टर्ड। ट्राइफेड ने 79 कारीगर मेलों और 50 प्रदर्शनियों का आयोजन किया।
- प्रत्येक वन धन विकास केंद्र क्लस्टर में 15 आदिवासी स्वयं सहायता समूह शामिल हैं, जिनके 300 लाभार्थी हैं। इस पहल में प्रति क्लस्टर 15 लाख रुपये दिए जाते हैं।

75 से अधिक जीआई टैग के साथ जनजातीय उत्पादों को नई वैश्विक पहचान मिली है।

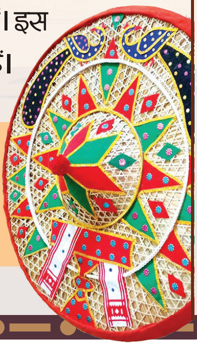

अराकू कॉफी

- अराकू कॉफी की 2017 में पेरिस में पहली आर्गेनिक कॉफी शॉप खोली गई। पहली बार छत्तीसगढ़ से महुआ के फूलों को फ्रांस निर्यात किया गया।
- आदिवासी संस्कृति, भाषा और परंपरा को बढ़ावा देने एवं दस्तावेजीकरण के लिए देश भर में 300 से अधिक आदिवासी हेरिटेज कंजर्वेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं।
- अप्रैल 2025 में धरती आबा ट्राइबप्रेन्योर्स कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें 45 आदिवासी स्टार्टअप को नवाचारों का प्रदर्शन करने और निवेशकों तथा स्टार्टअप नेताओं के साथ नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ लाया गया।
- दो स्टार्टअप को राष्ट्रीय मान्यता मिली। सिक्किम के ऑवर गेस्ट ट्रैवल्स ने पूर्वोत्तर भारत के पहले ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर के रूप में डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर अवॉर्ड जीता। वहीं, नगुरी ऑर्गेनिक को सतत कृषि कार्य के लिए एग्रीटेक अवार्ड मिला।
- अनुसूचित जनजातियों के लिए 50 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फंड स्थापित। आईआईएम, आईआईटी, आईएफसीआई और मेटा जैसे प्रमुख संस्थानों के साथ साझेदारी।

उनकी आस्था, उनके आत्मसम्मान और उनकी संस्कृति की रक्षा राष्ट्र का संकल्प बना है। एक साधारण जनजातीय पृष्ठभूमि, भारत की सभ्यता, संवैधानिक मूल्यों और लोकतंत्र में स्थायी विश्वास की अभिव्यक्ति बनीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु नए भारत के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्पों की मिसाल हैं, जिसे उन्होंने सदैव अपने कर्तव्य में सर्वोपरि रखा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के जीवन का हर पहलू एक ऐसी कहानी की तरह है जो आने वाली पीढ़ी को प्रेरित और प्रभावित करती रहेगी।

वोकल फॉर लोकल से जनजातीय उत्थान

'वोकल फॉर लोकल' आदिवासी कला कौशल को आय का साधन बना रहा है। दशकों पुराने कानून जो आदिवासी लोगों को बांस जैसी वन-उपज को काटने से रोकते थे, उन्हें बदलकर

जनजातीय विरासत को सम्मान

पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के इतिहास के साथ समृद्ध सांस्कृतिक विविधता में जनजातीय क्षेत्रों और उनके नायकों के योगदान को नमन किया और शुरूआत हुई एक मौन क्रांति की, जिसने न केवल जनजातीय विरासत को पुनर्जीवित किया, बल्कि गर्व के साथ सम्मान की परंपरा को किया स्थापित...

सांस्कृतिक और ऐतिहासिक सुधार...

- गुमनाम नायकों के बलिदान को कभी भुलाया न जा सके, इसलिए भारत सरकार ने देश की स्वतंत्रता के 75 वर्षों का जश्न मनाते हुए वर्ष 2021 में आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिवस 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया। सांस्कृतिक सुधार की दिशा में यह केंद्र सरकार का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा कदम था।
- 2024 का जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती थी। इसमें आदिवासी विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से गौरव, भागीदारी और नीति-संचालित कार्रवाई का देशव्यापी प्रदर्शन देखा गया।

- जनजातीय समुदाय के वीर योद्धाओं की भूली-बिसरी कहानियों को सामने लाने के लिए आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को मंजूरी दी गई। इसके तहत 10 राज्यों में 11 संग्रहालय की स्थापना की शुरुआत की गई। इनमें से 3 का निर्माण पूरा हो चुका है।
- मध्य प्रदेश के भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति और मणिपुर के कैमाई रेलवे स्टेशन का नाम रानी गाइदिन्ल्यू के नाम पर रखा गया। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर सराय काले खां चौक का नाम बदलकर 'भगवान बिरसा मुंडा चौक' करने का निर्णय लिया।
- पीएम मोदी ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया। दशकों तक यह स्थल अधिकांश भारतीयों के लिए अज्ञात रहा।

प्रतिनिधित्व का ऐतिहासिक पल...

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुईं। देश में पहली बार जनजातीय समुदाय से किसी का शीर्ष पद पर आसीन होना उन करोड़ों सपनों और आकांक्षाओं की सामूहिक जीत है, जो अतीत की जड़ों को वर्तमान की उम्मीदों से जोड़ती है।

वन-उपज पर अधिकार दिए गए हैं। आज वन उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार अनेक नए प्रयास कर रही है। पहले केवल 12 वन उपज की एमएसपी पर खरीद होती थी लेकिन आज इस सूची में करीब-करीब 90 उत्पाद वन उपज के रूप में शामिल किए गए हैं। देश ने वन धन योजना के जरिए वन संपदा को आधुनिक अवसरों से जोड़ने का काम भी शुरू किया है। देश में 3 हजार से अधिक वन-धन विकास केंद्रों के साथ ही 50 हजार से ज्यादा वन-धन सेल्फ हेल्प ग्रुप भी काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की गई है। आकांक्षी जिले और आकांक्षी ब्लॉक के विकास के लिए जो अभियान देश चला रहा है, उसका भी बड़ा लाभ आदिवासी इलाकों को हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा पर जो जोर दिया गया है, उससे भी आदिवासी बच्चों को पढ़ाई में बहुत मदद मिलेगी।

आजादी की लड़ाई में आदिवासी समाज के अप्रतिम योगदान को हर

वैश्विक नेताओं को जनजातीय विरासत से जुड़े उपहार

- पीएम मोदी ने कई देश के नेताओं को जनजातीय कलाकृतियां भेंट कर भारतीय आदिवासी संस्कृति को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है।
- डोकरा कला, धातु की जटिल कारीगरी और गहरी ऐतिहासिक जड़ों के लिए जानी जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कुक आइलैंड्स और टोंगा के नेताओं को डोकरा कलाकृतियां उपहार में दीं।
- झारखंड की सोहराई पेंटिंग रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को और मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा को उपहार में दी।
- उज्बेकिस्तान और कोमोरोस के नेताओं को महाराष्ट्र की वारली पेंटिंग से सम्मानित किया गया।

सांस्कृतिक संरक्षण और संवर्धन

- केंद्र सरकार जनजातीय सांस्कृतिक विरासत भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण के लिए 29 जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता देती है। इसके लिए 2020-25 के दौरान 265.94 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
- 2014 से अब तक 10 नए जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के भवनों को मंजूरी दी है।
- जनजातीय शोध संस्थान जनजातीय छात्रों के लिए शैक्षिक सामग्री विकसित करते हुए जनजातीय भाषाओं, पारंपरिक प्रथाओं और लोक कलाओं पर शोध और दस्तावेजीकरण करते हैं।
- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यवस्था की गई है कि विद्यालयों में कम से कम कक्षा 5 तक (और जहां संभव हो उससे आगे) मातृभाषा/स्थानीय भाषा में शिक्षा हो।
- भारत में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अनुवादक आदिवाणी एप लॉन्च किया गया। यह प्लेटफॉर्म भाषाई अंतर को पाटने और जनजातीय बोलियों में संचार को मजबूत करने के लिए विकसित किया गया है।

जनजातीय नायकों को पद्म सम्मान

- वर्ष 2014 के बाद केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों की नामांकन प्रक्रिया को पूरी तरह बदल कर पहली बार इन्हें आम आदमी का पुरस्कार बनाया।
- नतीजा... भील चित्रकार, गोंड लकड़ी के कारीगर, बैगा शिल्पकार और पर्यावरण की रक्षा में समर्पित जनजातीय परंपराओं के संरक्षक जैसे संस्कृति के मौन प्रहरी अब राष्ट्रीय चेतना का अभिन्न अंग बन चुके हैं।
- जनजातीय समुदाय के 100 से अधिक लोगों को अभी तक पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।

जनजातीय सशक्तीकरण की ओर कदम

- भारत के आदिवासी समुदायों के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता, सांस्कृतिक संरक्षण और सामाजिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव के रूप में 2017 में आदि महोत्सव की शुरुआत की गई।
- दिल्ली समेत देश के कई शहरों में जनजातीय कार्य मंत्रालय और ट्राइफेड की ओर से इसका आयोजन किया जाता है। यह महोत्सव भारत की समृद्ध जनजातीय कला, संस्कृति, हस्तशिल्प, व्यंजन और लोककला को मुख्यधारा से जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- देश के प्रमुख शहरों में 38 आदि महोत्सव आयोजित किए गए हैं।

घर तक पहुंचाने के लिए अमृत महोत्सव में अनगिनत प्रयास किए गए हैं। आजादी के बाद पहली बार, देश में आदिवासी गौरव और विरासत को प्रदर्शित करने के लिए आदिवासी संग्रहालय बनाए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के लंबसिंगी में 'अल्लूरी सीताराम राजू मेमोरियल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय' भी बनाया जा रहा है। विदेशी हुकूमत ने आदिवासियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार किए, उनकी संस्कृति को नष्ट करने के प्रयास किए, लेकिन अब उन बलिदानों का स्मरण आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। वन संपदा आदिवासी समाज के युवाओं के लिए रोजगार और अवसरों का माध्यम बने, इसके लिए केंद्र सरकार के स्तर से अनेक प्रयास हो रहे हैं।

परंपरा की वाहक जनजातियों को नई पहचान

बीते कुछ वर्षों से पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में जनजातीय समुदाय और जनजातीय जीवन से जुड़े लोगों का अच्छा-खासा

प्रतिनिधित्व रहता है। जनजातीय जीवन, शहरों की भाग-दौड़ से अलग होता है, उसकी चुनौतियां भी अलग होती हैं। इसके बावजूद जनजातीय समाज, अपनी परंपराओं को सहेजने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जनजातीय समुदायों से जुड़ी चीजों के संरक्षण और उन पर शोध के प्रयास भी होते हैं। ऐसे ही टोटो, हो, कुइ, कुवी और मांडा जैसी जनजातीय भाषाओं पर काम करने वाले कई व्यक्तित्वों को पद्म पुरस्कार मिले हैं। धानीराम टोटो, जानुम सिंह सोय और बी. रामकृष्ण रेड्डी के नाम से अब तो पूरा देश परिचित हो गया है। सिद्धी, जारवा और ओंगे जैसी आदि-जनजाति के साथ काम करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया। जैसे - हीराबाई लोबी, रतन चंद्र कार और ईश्वर चंद्र वर्मा। जनजातीय समुदाय भारत की धरती, भारत की विरासत का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। देश और समाज के विकास में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। उनके लिए काम करने वाले व्यक्तित्वों का सम्मान, नई पीढ़ी को भी प्रेरित करता है। इतना ही नहीं, पद्म पुरस्कारों की गूंज उन इलाकों में भी सुनाई दे रही है जो कभी नक्सल प्रभावित हुआ करते थे। अब केंद्र सरकार ने नक्सल मुक्त भारत की तारीख 31 मार्च 2026 निर्धारित कर दी है। अपने प्रयासों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गुमराह युवकों को सही राह दिखाने वालों को भी पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इसके लिए कांकेर में लकड़ी पर नक्काशी करने वाले अजय कुमार मंडावी और गढ़चिरौली के प्रसिद्ध झाडीपट्टी रंगभूमि से जुड़े परशुराम कोमाजी खुणे को भी यह सम्मान मिला है। इसी प्रकार पूर्वोत्तर में अपनी संस्कृति के संरक्षण में जुटे रामकुईवांगबे निउमे, बिक्रम बहादुर जमातिया और करमा वांगचु को भी सम्मानित किया गया है।

विकास और विरासत साथ-साथ

अठारहवीं सदी से ही, जनजातीय समाज ने, ब्रिटिश हुकूमत के अन्याय का संगठित विरोध किया था। वर्ष 1855 में संथाल-हूल का नेतृत्व करने वाले बहादुर भाइयों सिद्धो-कान्हू और चांद-भैरव के साथ फूलो-झानो जैसी वीरांगना बहनों ने भी असाधारण साहस का परिचय दिया था। जनजातीय लोगों के गौरवशाली योगदान से देशवासियों को परिचित कराने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। जनजातीय महानायकों की स्मृति में देश के विभिन्न क्षेत्रों में संग्रहालय बनाए जा रहे हैं। रांची में भगवान बिरसा मुंडा का संग्रहालय एक तीर्थ स्थल की तरह सम्मानित हो गया है। राष्ट्रपति भवन में भी 'जनजातीय दर्पण' नामक संग्रहालय विकसित किया गया है। बीते वर्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने जनजातीय गौरव दिवस पर कहा था, "मैं तिलका मांझी तथा भगवान बिरसा मुंडा से लेकर लक्ष्मण नायक जैसे अनेक जनजातीय महानायकों की कहानियां सुनते हुए बड़ी हुई। लेकिन, सामान्य लोगों के बीच उन महानायकों के विषय में उतनी जानकारी नहीं होती थी। सरकार के प्रयासों द्वारा अब जनजातीय स्वाधीनता सेनानियों की कथाओं से लोग भली-भांति परिचित होने लगे हैं। युगों-युगों से, जनजातीय समाज के लोग, हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को समृद्ध बनाते रहे

आजादी का अमृत महोत्सव...

सम्मान की ओर एक और कदम

उलगुलान आंदोलन, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, भील आंदोलन जैसे आंदोलन और विद्रोहों से भारत की आजादी के लिए जनजातीय समाज ने बहुत बड़ा योगदान दिया। आजादी के अमृत महोत्सव में अल्लूरी सीतारमन राजू, तिलका मांझी, सिधू-कान्हू मुर्मु, बुधू भगत सहित कई गुमनाम नायकों को किया गया याद...

- **रानी दुर्गावती स्मरणोत्सवः** पीएम मोदी ने रानी दुर्गावती के 500वें जन्म शताब्दी समारोह के तहत जबलपुर में 'वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान' का भूमि पूजन किया।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2021 को 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत 'जनजातीय गौरव दिवस' के अवसर पर 50 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखी।
- 15 नवंबर 2021 को नागालैंड के कोहिमा में आजादी का अमृत महोत्सव के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वदेशी खेल का आयोजन किया गया।

जनजातीय गौरव वर्ष विरासत का जश्न

धरती आबा यानी बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुई क्रांति ने न केवल ब्रिटिश अत्याचार को कड़ी चुनौती दी बल्कि जनता को जागृत भी किया। पीएम मोदी ने बिहार के जमुई में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 15 नवंबर 2024 को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष समारोह की शुरुआत की, जिसका समापन 15 नवंबर को है...

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष समारोह की शुरुआत की।
- पीएम मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट का अनावरण किया।
- केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भगवान बिरसा मुंडा के 150वें जयंती वर्ष के अवसर पर 15 नवंबर 2024 को नई दिल्ली के बांसेरा उद्यान में उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण किया।
- जनजातीय गौरव वर्ष के संदर्भ में आदि कर्मयोगी अभियान शुरू। यह एक अग्रणी उत्तरदायी शासन मिशन है जिसका उद्देश्य दुनिया का सबसे बड़ा जमीनी स्तर का आदिवासी नेतृत्व कार्यक्रम विकसित करना है।
- आदि कर्मयोगी अभियान पहल से संबंधित मंत्रालयों को भी परिचित कराया गया ताकि उन्हें इसके उद्देश्यों और अपेक्षित प्रभावों के बारे में जागरूक किया जा सके।
- बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बिरसा मुंडा जनजातीय उपवन बनाने की घोषणा। उपवनों में 500 से एक हजार पेड़ लगाने का लक्ष्य।
- छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित, जिसमें केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने माय भारत युवा स्वयंसेवकों के साथ 'माटी के वीर' पदयात्रा (पैदल मार्च) का नेतृत्व किया।
- 2024 के जनजातीय गौरव दिवस में 1 करोड़ से अधिक लोगों की बड़े पैमाने पर आभासी (वर्चुअल) भागीदारी देखी गई।
- इस दौरान, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, कला और संस्कृति और अन्य विषयों को कवर करते हुए देश भर में 46 हजार से अधिक गतिविधियां आयोजित की गईं।
- आदि महोत्सव और धरती-आबा ट्राइबप्रेन्योर्स जैसे कार्यक्रमों ने आदिवासी प्रतिभाओं का जश्न मनाया, जबकि 29 आदिवासी अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) ने त्योहारों, सेमिनार और छात्र-नेतृत्व वाले कार्यक्रमों के आयोजन में भाग लिया।

हैं। रामायण की कथा में हमारे समाज के शाश्वत जीवन-मूल्य दिखाई देते हैं। अपने लंबे वनवास के दौरान, प्रभु श्रीराम, जनजातीय समाज के लोगों के साथ, उन्हीं की तरह रहे। भगवान श्रीराम ने वनवासियों को अपनाया और वनवासियों ने प्रभु श्रीराम को अपनाया। जनजातीय समाज का यह अपनापन और समरसता ही हमारी संस्कृति और सभ्यता का आधार है।" अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय जनजातीय भाषा 'संथाली' को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया था।

इतना ही नहीं, झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय व उद्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया। देशभर में 200 करोड़ रुपये के बजट से जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों की स्थापना गुजरात, झारखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, मध्य देश, तेलंगाना, मणिपुर, मिजोरम और गोवा में होगी जिसकी मंजूरी दी गई है।

राष्ट्रीय आदिवासी संग्रहालय गुजरात के नर्मदा जिले के गरुड़ेश्वर में स्थापित किया जा रहा है, यह संग्रहालय स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से लगभग 6 किमी दूर है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित आदिवासियों के प्रमुख तीर्थ स्थल मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया गया। जनजातीय आबादी की अधिकता वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र में पिछले 11 वर्षों में एक्ट ईस्ट नीति के तहत विकास पर बल दिया गया। सभी मंत्रालयों की योजनाओं में 10% बजट पूर्वोत्तर के लिए अनिवार्य कर अष्टलक्ष्मी को राष्ट्रीय प्रगति में शामिल किया गया। आजादी के आंदोलन में अविस्मरणीय योगदान और बलिदान देने वाले आदिवासी समाज को विकास की मुख्यधारा में जोड़ने, सामाजिक आर्थिक उत्थान और राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने का काम तेजी से किया जा रहा है।

सामाजिक स्तर में दिखने लगा सुधार

जनजातीय विकास का परिणाम धरातल पर भी दिखने लगा है। अनुसूचित जनजातियों (अजजा) की साक्षरता दर 2011 की जनगणना में 59% थी जो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट (जुलाई 2023-जून 2024) के अनुसार बढ़कर 73.40% हो गई है। प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) और प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) योजनाओं के अंतर्गत अब तक कुल 4,661 वन धन विकास केंद्रों को मंजूरी दी गई है। अपनी शुरुआत से ही वन धन योजना ने पूरे भारत में आदिवासी समुदायों की आजीविका में जबरदस्त सुधार किया है। इस पहल से 11.83 लाख से अधिक आदिवासी व्यक्तियों को लाभ हुआ है और उनकी आय में वृद्धि हुई है। इस योजना ने आर्थिक अवसर प्रदान किए हैं और वन-आश्रित समुदायों को आत्मनिर्भर बनने के लिए सशक्त बनाया है। वित्त वर्ष 2022-23 से जून 2025 तक, स्वयं सहायता समूहों की 65,949 महिला सदस्यों की पहचान कर उन्हें प्रशिक्षित किया गया है। जनजातीय सशक्तीकरण के लिए आदि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जहां आदिवासी कारीगर, बुनकर, कुम्हार, कठपुतली बनाने वाले और कढ़ाई करने वालों की उत्कृष्ट शिल्प परंपराएं सभी एक ही स्थान पर एकत्रित होती हैं। जनजातीय उत्पादों के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहायता कार्यक्रम के तहत, ट्राइफेड अपने पोर्टल www.tribesindia.com से आदिवासी उत्पादों की बिक्री को ई-कॉमर्स के माध्यम से बढ़ावा देता है। इनमें केंद्र सरकार की सामाजिक सरोकार वाली योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया गया है।

जनजातीय वर्ग के उत्थान में कदम लगातार उठ रहे हैं। केंद्र सरकार ने 728 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की स्थापना को स्वीकृति दी है। जबकि वर्ष 2013-14 में सिर्फ 167 विद्यालय स्वीकृत थे। अब केंद्र सरकार का लक्ष्य 2026 तक 740 एकलव्य मॉडल विद्यालय शुरू करने का है, जिसके लिए लगातार काम जारी है। अगर आंकड़ों में देखें तो वर्ष 2013-14 में 119 स्कूल में पढ़ाई होती थी, अब इसकी संख्या 485 से अधिक हो चुकी है। तेलंगाना में सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को अक्टूबर 2023 में कैबिनेट ने मंजूरी दी। वर्ष 2014 के बाद से देश भर में 10 आदिवासी शोध संस्थान को मंजूरी दी गई है। टॉप क्लास छात्रवृति योजना के तहत हर साल छात्रों को आईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसे शीर्ष संस्थानों में दाखिले के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। जनजातियों का निवास मुख्य रूप से खनन प्रभावित क्षेत्रों में है, किंतु उन्हें कभी खनन से होने वाली आय में हिस्सेदारी नहीं मिलती थी। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की स्थापना से विसंगति दूर हुई जिससे मिलने वाले हजारों करोड़ की राशि एकत्रित हुई है और इसका उपयोग जनजातीय क्षेत्रों के विकास में हो रहा है।

आदिवासियों का कलात्मक खजाना जी-20 में दिखा

भारत की अध्यक्षता में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन में समृद्ध जनजातीय विरासत और शिल्प कौशल एवं श्रेष्ठ उत्पादों ने दुनिया का ध्यान खींचा। पद्मश्री से सम्मानित परेशभाई जयंतीभाई राठवा ने पिथौरा कला का लाइव प्रदर्शन किया। गुजरात और एमपी के राठवा, भिलाला, नाइक और भील जनजातियों द्वारा यह कला प्रचारित है। लोंगपी पॉटरी कला, छत्तीसगढ़ के बस्तर की गोंड जनजाति द्वारा बनाई गई सुलूर बांस की पवन बांसुरी, गोंड पेंटिंग, गुजरात की भील और पटेलिया जनजाति द्वारा बनाई गई हैंगिंग्स, मीना जनजाति की धातु अम्बाबाड़ी के रूप में जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और विरासत को विश्व समुदाय के सामने पेश किया गया। देश के निर्यात में हैंडीक्राफ्ट का हिस्सा बढ़ रहा है। करीब 30 फीसदी की दर से हुई इस बढ़ोतरी में आदिवासी हस्तशिल्प यानी ट्राइफेड प्रोडक्ट्स की बड़ी हिस्सेदारी है।

निश्चित तौर से केंद्र सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों और लोगों के मन को छूने की पहल की है, ताकि उन्हें भी आत्मनिर्भर भारत का सारथी बनाया जा सके क्योंकि सामाजिक न्याय का अर्थ है- समाज के हर वर्ग को समान अवसर मिले, जीवन की मौलिक जरूरतों से कोई भी वंचित न रहे।

मुंबई को दूसरे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे समेत 69 हजार करोड़ रुपये की सौगात

गति+प्रगति = विकसित भारत

विकसित भारत...यानी जहां गति के साथ प्रगति भी हो...जहां लोकहित सर्वोपरि हो और सरकार की योजनाएं देशवासियों का जीवन आसान बनाएं। बीते 11 वर्ष में भारत ने नवनिर्माण की इस यात्रा को जीया है...वंदे भारत ट्रेन, चौड़े हाइवे-एक्सप्रेसवे, पहाड़ों पर सुरंगें और समुद्री किनारे को जोड़ते सी ब्रिज... यह देश की गति और प्रगति दिखा रहे हैं। देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के इस महायज्ञ में एक और कड़ी 8 अक्टूबर को मुंबई में जुड़ी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ पहली अंडरग्राउंड मेट्रो सहित 69 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का किया उद्घाटन और लोकार्पण...

भारत की आर्थिक राजधानी के अलावा दूसरे सबसे बड़े और वाइब्रेंट शहर के साथ मुंबई भागती-दौड़ती जिंदगी का प्रतीक भी है। इस व्यस्त शहर में यात्रा आसान हो, लोगों का समय बचे इसी उद्देश्य से लगातार परिवहन के हर साधन के विस्तार पर केंद्र सरकार काम कर रही है। इसी कड़ी में बने नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, मुंबई मेट्रो लाइन-3 के चरण 2बी, मुंबई की पहली पूर्णतः भूमिगत मेट्रो लाइन-3(एक्वा लाइन) और कॉमन मोबिलिटी एप 'मुंबई वन' का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "मुंबई का लंबा इंतजार खत्म हुआ है।"

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है, जिसमें विकसित भारत की झलक है। यह छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर बना है, इसका आकार कमल के फूल जैसा है, यानी ये संस्कृति और समृद्धि का जीवंत प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस नए एयरपोर्ट से महाराष्ट्र के किसान यूरोप और मिडिल ईस्ट के सुपरमार्केट से भी जुड़ जाएंगे। किसान की ताजा उपज, फल-फूल, सब्जी और मछुआरों के उत्पाद, तेजी से ग्लोबल मार्केट तक पहुंच पाएंगे। इस एयरपोर्ट से यहां आसपास के छोटे और लघु उद्योगों के लिए एक्सपोर्ट की लागत कम होगी। यहां निवेश बढ़ेगा, नए उद्योग, नए उद्यम लगेंगे।

देश का पहला हवाई अड्डा जो वाटर टैक्सी से जुड़ेगा

- नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की लागत लगभग 19,650 करोड़ रुपये है। अभी इसके पहले चरण का उद्घाटन हुआ है।
- यह भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना है, जिसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत विकसित किया गया है।
- यह मुंबई का दूसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसएमआईए) के साथ मिलकर काम करेगा, ताकि मुंबई वैश्विक बहु-हवाई अड्डा प्रणालियों की श्रेणी में शामिल हो सके।
- 1,160 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले इस हवाई अड्डे को दुनिया के सबसे कुशल हवाई अड्डों में से एक के रूप में डिजाइन किया गया है।
- यह सालाना 9 करोड़ यात्रियों को संभालने और 3.25 मिलियन मीट्रिक टन माल की दुलाई में सक्षम है।
- इस हवाई अड्डे की अनूठी सुविधाओं में एक स्वचालित मूवर शामिल है। एक ऐसी परिवहन प्रणाली, जो सभी चार यात्री टर्मिनलों को निर्बाध अंतर-टर्मिनल स्थानांतरण के लिए आपस में जोड़ेगी।
- एक लैंडसाइड स्वचालित मूवर भी शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को एकीकृत करेगा।
- हवाई अड्डे में स्थायी विमानन ईंधन के लिए समर्पित भंडारण होगा। लगभग 47 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा।
- पूरे शहर में सार्वजनिक संपर्क के लिए ईवी बस सेवाएं उपलब्ध होंगी।
- यह देश का ऐसा पहला हवाई अड्डा होगा, जो वाटर टैक्सी से जुड़ा होगा।

> मुंबई को अब अपना दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल गया है। यह एयरपोर्ट इस क्षेत्र को एशिया के सबसे बड़े कनेक्टिविटी हब के रूप में स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। मुंबई को पूरी तरह से अंडर ग्राउंड मेट्रो भी मिली है। इससे मुंबई में ट्रैवल और आसान होगा, लोगों का समय बचेगा।
>
> -नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

जब सपनों को सिद्ध करने का संकल्प हो, देशवासियों तक तेज विकास का लाभ पहुंचाने की इच्छाशक्ति हो तो नतीजे भी मिलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 में मैंने कहा था कि मेरा सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफर कर सके। इस सपने को पूरा करने के लिए सरकार ने गंभीरता से काम शुरू किया। बीते 11 साल में देश में एक के बाद एक नए एयरपोर्ट बनते चले गए। साल 2014 में देश में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे। आज भारत में इनकी संख्या बढ़कर 160 को पार कर गई है।

देश में नए एयरपोर्ट बनने और उड़ान योजना से लोगों को सुविधा तो मिली ही है, भारत दुनिया का तीसरा बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट भी बन गया है। भारत की एयरलाइन लगातार अपना विस्तार कर रही हैं। अकेले हिंदुस्तान से इन दिनों हवाई जहाज बनाने वाली कंपनियों के पास करीब-करीब 1 हजार नए हवाई जहाज का ऑर्डर

मुंबई को इन परियोजनाओं की भी सौगात

आचार्य अत्रे चौक से कफ परेड तक फैले मुंबई मेट्रो लाइन-3 के चरण 2बी का उद्घाटन। इसका निर्माण लगभग 12,200 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है।

- परियोजना का अंतिम चरण 2बी दक्षिण मुंबई के विरासत और सांस्कृतिक जिलों जैसे फोर्ट, काला घोड़ा और मरीन ड्राइव को निर्बाध परिवहन-संपर्क प्रदान करेगा। साथ ही, बॉम्बे हाई कोर्ट, मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नरीमन पॉइंट सहित प्रमुख प्रशासनिक एवं वित्तीय केंद्रों तक सीधी पहुंच प्रदान करेगा।

37,270 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली पूरी मुंबई मेट्रो लाइन 3 (एक्वा लाइन) भी राष्ट्र को समर्पित। यह मुंबई की पहली पूर्णतः भूमिगत मेट्रो लाइन है।

- कफ परेड से आरे जेवीएलआर तक 33.5 किलोमीटर लंबी 27 स्टेशनों वाली मुंबई मेट्रो लाइन-3, प्रतिदिन 13 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करेगी।
- मेट्रो लाइन-3 को रेलवे, हवाई अड्डों, अन्य मेट्रो लाइनों और मोनोरेल सेवाओं के साथ इंटीग्रेट करके डिजाइन किया गया है, जिससे अंतिम स्थान तक परिवहन-संपर्क सुविधा में सुधार होगा, भीड़भाड़ कम होगी।

प्रधानमंत्री ने मेट्रो, मोनोरेल, उपनगरीय रेलवे और बस पीटीओ के 11 सार्वजनिक परिवहन ऑपरेटरों के लिए एकीकृत कॉमन मोबिलिटी एप 'मुंबई वन' भी लॉन्च किया।

- मुंबई वन एप में मुंबई मेट्रो लाइन 2ए और 7, मुंबई मेट्रो लाइन 3, मुंबई मेट्रो लाइन 1, मुंबई मोनोरेल, नवी मुंबई मेट्रो, मुंबई उपनगरीय रेलवे, बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति और परिवहन (बेस्ट), ठाणे नगर परिवहन, मीरा भयंदर नगर परिवहन, कल्याण डोंबिवली नगर परिवहन और नवी मुंबई नगर परिवहन शामिल हैं।
- अब मुंबई वालों को टिकट के लिए घंटों लाइन में खड़ा नहीं रहना होगा। मुंबई वन एप से एक बार टिकट लेकर उसी टिकट से लोकल, बस, मेट्रो या टैक्सी में सफर कर सकेंगे।
- यह एप देरी, वैकल्पिक मार्गों और अनुमानित आगमन समय के बारे में वास्तविक समय का अपडेट भी प्रदान करता है।

प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के कौशल, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग की एक अग्रणी पहल, अल्पकालिक रोजगार योग्यता कार्यक्रम (एसटीईपी) का भी उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम 400 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और 150 सरकारी तकनीकी उच्च विद्यालयों में लागू किया जाएगा।

- यह रोजगार योग्यता बढ़ाने के लिए कौशल विकास को उद्योग की आवश्यकताओं के साथ जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है। एसटीईपी के तहत 2,500 नए प्रशिक्षण बैच स्थापित किए जाएंगे, जिनमें महिलाओं के लिए 364 विशेष बैच और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी), सौर ऊर्जा और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसे उभरते प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों के लिए 408 बैच शामिल हैं।

बुक पड़ा है। इससे नए पायलट, केबिन क्रू, इंजीनियर, ग्राउंड वर्कर के लिए नए अवसर बन रहे हैं। जब जहाज बढ़ते हैं तो मेंटेनेंस व रिपेयर का काम भी बढ़ता है। इसके लिए भी केंद्र सरकार देश में ही नई सुविधाएं बना रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस मेट्रो लाइन का लोकार्पण किया, उसका भूमि पूजन कई वर्ष पहले हुआ था। लेकिन एक-एक मिनट का महत्व रखने वाली मुंबई को यह मेट्रो तब मिली जब डबल इंजन की सरकार आई। अब ये मेट्रो लाइन बनने से दो-ढाई घंटे का सफर 30-40 मिनट में पूरा हो जाएगा। इस देरी का उल्लेख करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "हम उन संस्कारों में पले बढ़े हैं, जहां राष्ट्रनीति ही राजनीति का आधार है। हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगने वाला एक-एक पैसा देशवासियों की सुविधा और सामर्थ्य को बढ़ाने का माध्यम है।"■

प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए **QR** कोड स्कैन करें।

मेड इन इंडिया

वैश्विक मंच पर भारत की मोबाइल क्रांति

नीति-निर्माण, तकनीकी निवेश और रणनीतिक साझेदारियों के बल पर देश ने बीते एक दशक में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को एक नए मुकाम तक पहुंचाया है। भारत की मोबाइल निर्माण यात्रा अब केवल एक औद्योगिक पहल नहीं बल्कि तकनीकी की आत्मनिर्भरता की प्रेरक कहानी बन गई है। आत्मनिर्भरता की यही सोच अब 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' की सच्चाई बन चुकी है। यह परिवर्तन न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि भारत की वैश्विक तकनीकी ताकत को भी दर्शाता है। इसी विश्वास को आगे बढ़ाते हुए 8 अक्टूबर को 9वीं मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सुरक्षित हाथों में है भारत का तकनीकी भविष्य...

बाजार की मजबूती के साथ-साथ, भारत के पास जनशक्ति, गतिशीलता और प्रगतिशील सोच भी है। इसी का परिणाम है कि भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार और 5जी बाजार वाला देश बना है। देश को इस उपलब्धि तक पहुंचाने में यहां के युवाओं की बड़ी भागीदारी है। इसमें केंद्र सरकार भी उन्हें हर संभव मदद दे रही है। 5जी, 6जी, उन्नत ऑप्टिकल संचार और टेरा-हट्र्ज जैसी तकनीकों के परीक्षण केंद्रों को सरकार वित्तीय सहायता दे रही है। सरकार की पहल से ही स्टार्टअप और प्रमुख शोध संस्थानों के बीच साझेदारी को सुगम बनाया जा रहा है। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि भारत वैश्विक पटल पर प्रभावी मंच के रूप में स्थापित हुआ है और दुनिया भारत की ओर देख रही है।

दिल्ली के यशोभूमि में 8 से 11 अक्टूबर तक इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म विषय पर दूरसंचार विभाग और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन किया गया। एशिया के सबसे बड़े दूरसंचार, मीडिया और प्रौद्योगिकी आयोजन 'इंडिया मोबाइल कांग्रेस-2025' में कई स्टार्टअप ने वित्तीय धोखाधड़ी रोकथाम, क्वांटम संचार, 6जी, ऑप्टिकल संचार और सेमीकंडक्टर सहित कई अन्य विषयों पर गंभीर चर्चा की। जिसे सुनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के तकनीक-प्रेमियों ने देश को कुछ वर्षों में ही एशिया के सबसे बड़े

एक कंपनी से 3.5 लाख रोजगार

प्रधानमंत्री मोदी ने एक प्रमुख स्मार्टफोन कंपनी के हाल के आंकड़ों का उदाहरण देते हुए बताया कि आज 45 भारतीय कंपनियां उस एक बड़ी कंपनी की सप्लाई चेन से जुड़ी है। इससे करीब 3.5 लाख रोजगार देश में सृजित हुए हैं। यही नहीं, इसके अलावा भी देश में कितनी ही कंपनी बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने बड़े स्तर पर रोजगार का सृजन हो रहा है।

मोबाइल कांग्रेस में 150 से ज्यादा देशों ने लिया हिस्सा

इंडियन मोबाइल कांग्रेस-2025 में 150 से ज्यादा देशों के 1.5 लाख से ज्यादा अतिथि, 7,000 से ज्यादा वैश्विक प्रतिनिधि और 400 से ज्यादा कंपनी ने भाग लिया। 5जी/6जी, एआई, स्मार्ट मोबिलिटी, साइबर सुरक्षा, क्वांटम कंप्यूटिंग और हरित प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा हुई।

देश भर में 5जी कवरेज

- अब देश के लगभग हर जिले में 5जी कवरेज है।
- वर्ष 2014 से इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में छह गुना वृद्धि हुई है।
- मोबाइल फोन निर्माण में 28 गुना वृद्धि हुई है जबकि निर्यात में 127 गुना की वृद्धि हुई है।
- पिछले एक दशक में, मोबाइल फोन निर्माण क्षेत्र ने लाखों प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए हैं।

भारत ने अपना मेड इन इंडिया 4जी स्टैक लॉन्च किया है, यह देश के लिए एक बड़ी स्वदेशी उपलब्धि है, इसके साथ ही भारत दुनिया के उन पांच देशों की सूची में शामिल हो गया है जिनके पास यह क्षमता है।

भारत में बने आईफोन

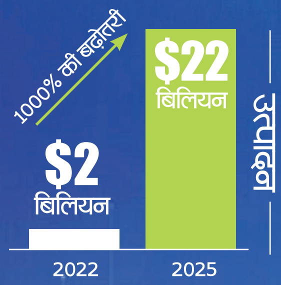

निर्यात (अप्रैल से सितंबर)

> दुनिया का दूसरा बड़ा टेलीकॉम मार्केट हमारे पास है। दूसरा सबसे बड़ा 5जी मार्केट यहां है। हमारे पास मैनपावर भी है, मोबिलिटी भी है और माइंडसेट भी है।
>
> *- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री*

डिजिटल प्रौद्योगिकी मंच के रूप में स्थापित किया है। इनोवेटर और स्टार्टअप ने इस विकास को गति दी है जो देश की क्षमता के साथ दृढ़ता से खड़ी सरकार द्वारा संभव हुआ है।

पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस, दूरसंचार क्षेत्र में भारत की सफलता और आत्मनिर्भर भारत के विजन की मजबूती को दर्शाता है। भारत ने हाल ही में अपना मेड-इन-इंडिया 4जी स्टैक लांच किया है जो एक बड़ी स्वदेशी उपलब्धि है। इसके साथ ही भारत अब इस क्षमता वाले विश्व के पांच देशों की सूची में शामिल हो गया है। जो देश कभी 2जी से जूझ रहा था वह अब स्वदेशी 4जी और 5जी स्टैक के माध्यम से न केवल निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा बल्कि अपने नागरिकों को हाई-स्पीड इंटरनेट और विश्वसनीय सेवाएं भी प्रदान कर रहा है। जिस दिन भारत में 4जी स्टैक लांच हुआ उस दिन, देश भर में लगभग एक लाख 4जी टावर एक साथ सक्रिय किए गए जिससे दो करोड़ से ज्यादा लोग भारत के डिजिटल आंदोलन का हिस्सा बने। दरअसल पहले दूर-दराज के कई क्षेत्र ऐसे थे जहां डिजिटल कनेक्टिविटी कमजोर थी लेकिन अब यहां इंटरनेट की मजबूत पहुंच सुनिश्चित हुई है।■

प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

पीएम-सेतु : कौशल और भविष्य के अवसरों को जोड़ने वाला सेतु

भारत दुनिया के युवा देशों में से एक है। युवाओं का सामर्थ्य और कौशल बढ़ता है तो राष्ट्र मजबूत होता है। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने कौशल विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 अक्टूबर को देश के युवाओं को पीएम सेतु योजना समेत 62 हजार करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं का उपहार दिया। यह योजना देश भर के 1,000 आईटीआई संस्थानों में विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराएगी ताकि युवाओं को कौशल, उद्योग आधारित शिक्षा और रोजगार सृजन के मिलें अधिक अवसर...

भारत ज्ञान और कौशल का देश है। यही बौद्धिक शक्ति राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है। जब यह कौशल एवं ज्ञान देश की आवश्यकताओं से जुड़ जाता है तो इनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच हमेशा रही कि जब तक हम श्रम और हुनर को प्रतिष्ठा नहीं देंगे, उन्हें सार्वजनिक जीवन में सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक शायद वे अपने आप को कम महसूस करेंगे। यही कारण है कि अब राष्ट्र श्रमेव जयते और श्रमेव पूज्यते को जीवंत कर रहा है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कौशल दीक्षांत समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज 21वीं सदी की मांग है कि हम देश की जरूरत को ध्यान में रखते हुए लोकल टैलेंट, लोकल रिसोर्सेज, लोकल स्किल्स और लोकल नॉलेज को तेजी से आगे बढ़ाएं। इसमें हमारे हजारों

पीएम सेतु यानी भविष्य के उद्योगों के लिए करियर-लॉन्चिंग हब

- पीएम सेतु योजना भविष्य के उद्योगों के लिए करियर-लॉन्चिंग हब तैयार करने में मदद करेगी। इसमें अपग्रेडेड आईटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार परिवर्तन योजना में देश भर के 1,000 सरकारी आईटीआई का हब-एंड-स्पोक मॉडल में उन्नयन करने की परिकल्पना की गई है। इसमें 200 हब आईटीआई और 800 स्पोक आईटीआई शामिल हैं।
- प्रत्येक हब औसतन चार स्पोक से जुड़ा होगा, जिससे उन्नत बुनियादी ढांचे, आधुनिक ट्रेडों, डिजिटल लर्निंग सिस्टम और इनक्यूबेशन सुविधाओं से लैस क्लस्टर बनेंगे।
- उद्योग जगत के प्रमुख साझेदार, बाजार की मांग के अनुरूप परिणाम-आधारित कौशल विकास को सुनिश्चित करते हुए इन समूहों का प्रबंधन करेंगे।
- हब में इनोवेशन केंद्र, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की सुविधाएं, उत्पादन इकाइयां और प्लेसमेंट सेवाएं होंगी।
- प्रथम चरण में पटना और दरभंगा के आईटीआई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- आईटीआई में अब आईटी, ड्रोन, ईवी, हेल्थ टेक, ग्रीन एनर्जी जैसे नए कोर्स भी शामिल।

> “ यह समय देश के हर युवा के लिए अवसरों से भरा हुआ है। हर चीज का विकल्प हो सकता है लेकिन कौशल, इनोवेशन और परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। यह सब कुछ भारत के सभी नौजवानों के पास है। आप सभी की शक्ति, विकसित भारत की शक्ति बनेगी।
>
> – नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

विकसित भारत की नींव होगी और भी मजबूत

प्रधानमंत्री मोदी ने 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 नवोदय विद्यालयों और 200 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में स्थापित 1,200 कौशल प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन किया। इससे विकसित भारत की नींव और भी मजबूत होगी।

170 ट्रेड में नौजवानों को आईटीआई में दी जा रही है ट्रेनिंग

आईटीआई में करीब 170 ट्रेड में नौजवानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बीते 11 सालों में डेढ़ करोड़ से ज्यादा नौजवान इन ट्रेड में प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। यानी उन्हें अलग-अलग क्षेत्रों के कौशल के साथ-साथ उसकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन से जोड़ा गया है। इन युवाओं को उनकी स्थानीय भाषाओं में कौशल प्रशिक्षण दिया गया। इस साल 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट में शामिल हुए हैं। साल 2014 तक हमारे देश में 10 हजार आईटीआई थे लेकिन बीते एक दशक में करीब 5,000 नए आईटीआई स्थापित किए गए हैं। इंडस्ट्री को आज कैसी स्किल चाहिए, 10 साल बाद किस प्रकार की स्किल की जरूरत होगी उस हिसाब से आईटीआई नेटवर्क को तैयार किया जा रहा है। इसलिए इंडस्ट्री और आईटीआई के बीच तालमेल को बढ़ाया जा रहा है।

आईटीआई की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारे आईटीआई इंडस्ट्रियल एजुकेशन के बेहतरीन संस्थान तो हैं ही, ये आत्मनिर्भर भारत की वर्कशॉप भी हैं। इसलिए हमारा फोकस इनकी संख्या बढ़ाने के साथ ही इनको लगातार अपग्रेड करने पर भी है।

जब कौशल बढ़ता है, देश आत्मनिर्भर होता है और निर्यात बढ़ता है तो रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। 2014 से पहले भारत को फ्रेजाइल फाइव इकोनॉमी कहा जाता था। यानी ग्रोथ कम थी, रोजगार भी बहुत कम थे लेकिन आज भारत टॉप थ्री इकोनॉमी बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। यानी मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार बढ़ रहे हैं। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल और डिफेंस सेक्टर में भी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। बड़े उद्योगों से लेकर एमएसएमई में अभूतपूर्व रोजगार का निर्माण हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन सबका बड़ा लाभ युवाओं को और विशेषकर आईटीआई के कुशल युवाओं को हुआ है। मुद्रा योजना ने भी करोड़ों नौजवानों को अपना रोजगार शुरू करने में मदद की है। अभी भारत सरकार ने एक लाख करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना भी लागू की है। इससे देश के करीब साढ़े तीन करोड़ नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार पाने में मदद मिलेगी।■

प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

600 रुपये तक बढ़ाई रबी फसलों की एमएसपी
57 नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे

विकसित भारत का निर्माण तभी संभव है, जब अन्नदाता सशक्त और खुशहाल हों। इसी विजन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किसानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाने का निर्णय लिया, वहीं दाल उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए 'दलहन आत्मनिर्भरता मिशन' को मंजूरी दी। इसके साथ ही देशभर में 57 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना सहित कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी दी स्वीकृति...

निर्णय : विपणन सीजन 2026-27 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी।

प्रभाव : एमएसपी में कुसुम के लिए 600 रुपये प्रति क्विंटल और मसूर के लिए 300 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। रेपसीड और सरसों, चना, जौ एवं गेहूं के लिए क्रमशः 250 रुपये प्रति क्विंटल, 225 रुपये प्रति क्विंटल, 170 रुपये प्रति क्विंटल और 160 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। रबी फसलों की एमएसपी में यह वृद्धि किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करेगी और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करेगी।

निर्णय : दाल उत्पादन बढ़ाएगा दलहन आत्मनिर्भरता मिशन।

प्रभाव : यह मिशन 2025-26 से 2030-31 तक छह वर्षों की अवधि में 11,440 करोड़ रुपये के वित्तीय खर्च के साथ क्रियान्वित किया जाएगा। इस मिशन से 2030-31 तक दलहन क्षेत्रफल को 310 लाख हेक्टेयर तक विस्तारित करने का लक्ष्य है। यह मिशन रोजगार सृजन भी करेगा। मिशन का उद्देश्य दलहन में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करना, आयात पर निर्भरता कम करना, किसानों की आय को बढ़ावा देना और विदेशी मुद्रा का संरक्षण करना है। मिशन की एक प्रमुख विशेषता, पीएम-आशा की मूल्य समर्थन योजना के तहत अरहर, उड़द और मसूर की अधिकतम खरीद सुनिश्चित करना है।

निर्णय : 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी।
प्रभाव : इन विद्यालयों की स्थापना के लिए निधियों की कुल अनुमानित आवश्यकता लगभग 5,862.55 करोड़ रुपये है जो 2026-27 से नौ वर्षों की अवधि के लिए है। भारत में अब तक 1285 केंद्रीय विद्यालय शुरू किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 3 केंद्रीय विद्यालय मास्को, काठमांडू और तेहरान में भी स्थापित है। 30 जून 2025 तक इनमें छात्रों का कुल नामांकन लगभग 13.62 लाख है। नए केंद्रीय विद्यालय की मंजूरी से कुल 4,617 प्रत्यक्ष स्थायी रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

निर्णय : केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी।
प्रभाव : महंगाई भत्ते में वृद्धि से केंद्र सरकार के लगभग 49.19 लाख कर्मचारी और 68.72 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। यह मूल वेतन/पेंशन के मौजूदा 55 प्रतिशत की दर में 3 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि है। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत दोनों में बढ़ोतरी से प्रति वर्ष राजकोष पर 10,083.96 करोड़ रुपये का संयुक्त प्रभाव पड़ेगा। यह 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी माना जाएगा।

निर्णय : असम में एनएच-715 के कालीबोर-नुमालीगढ़ सेक्शन के मौजूदा राजमार्ग को 4 लेन का बनाने और चौड़ा करने को मंजूरी।
प्रभाव : यह परियोजना इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और निर्माण (ईपीसी) मोड पर तैयार की जाएगी, जिसकी कुल लंबाई करीब 86 किलोमीटर और लागत 6,957 करोड़ रुपये होगी। इसमें काजीरंगा नेशनल पार्क खंड पर प्रस्तावित वन्यजीवों के प्रति अनुकूल पैमाने के अनुसार कार्यान्वयन शामिल है।
यह काजीरंगा नेशनल पार्क में पर्यटन को प्रोत्साहन देगा और व्यापार एवं औद्योगिक विकास के नए रास्ते खोलेगा। साथ ही, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

निर्णय : जैव-चिकित्सीय अनुसंधान करियर कार्यक्रम के तीसरे चरण को मंजूरी।
प्रभाव : यह कार्यक्रम अत्याधुनिक जैव-चिकित्सीय अनुसंधान के लिए शीर्ष स्तरीय वैज्ञानिक प्रतिभाओं को प्रोत्साहन प्रदान करेगा। इनोवेशन को व्यावहारिक समाधान में बदलने (ट्रांसलेशनल इनोवेशन) के लिए कई विषयों में अनुसंधान को बढ़ावा देगा। यह वैश्विक प्रभाव वाली विश्व स्तरीय जैव-चिकित्सीय अनुसंधान क्षमता विकसित करने के लिए उच्च-गुणवत्ता वाले अनुसंधान का समर्थन करने वाली प्रणालियों को भी मजबूत करेगा। साथ ही, वैज्ञानिक क्षमता में क्षेत्रीय असमानताओं को कम करेगा।

निर्णय : महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में चार मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं के प्रस्ताव को मंजूरी। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 894 किलोमीटर बढ़ेगा।
प्रभाव : स्वीकृत मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना से 3,633 गांव की लगभग 85.84 लाख की आबादी और मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के दो आकांक्षी जिलों विदिशा-राजनांदगांव तक संपर्क बढ़ेगा। 24,634 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत वाली परियोजनाएं 2030-31 तक पूरी होंगी। लाइन क्षमता में बढ़ोतरी से गतिशीलता बढ़ेगी, भीड़भाड़ कम होगी, परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता में सुधार होगा। इन परियोजनाओं से क्षेत्र के लोगों का व्यापक विकास होगा, यहां के लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। उनके लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

यह परियोजनाएं शामिल

- महाराष्ट्र में वर्धा - भुसावल के बीच 314 किलोमीटर लंबी तीसरी और चौथी लाइन
- महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में 84 किलोमीटर लंबी गोंदिया-डोंगरगढ़ चौथी लाइन
- गुजरात और मध्य प्रदेश में 259 किलोमीटर लंबी वडोदरा-रतलाम की तीसरी और चौथी लाइन
- मध्य प्रदेश में 237 किलोमीटर लंबी इटारसी-भोपाल-बीना चौथी लाइन।■

कैबिनेट के फैसलों पर प्रेस ब्रीफिंग देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

एमएसएमई के लिए पहल... आसान हुआ उन्नति का मार्ग

देश के सकल घरेलू उत्पाद में 30%, मैन्युफैक्चरिंग में 35% और निर्यात में 45% से अधिक के योगदान के साथ एमएसएमई सेक्टर भारत के वैश्विक व्यापार के इकोसिस्टम का महत्वपूर्ण भाग ही नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। देश की उन्नति के इस मार्ग को और मजबूती मिली 2 नवंबर 2018 को, जब एक साथ 12 घोषणाओं के संग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसएमई के सपनों को दिया नया विस्तार...

भारत की अर्थव्यवस्था की असली ताकत गांवों, कस्बों और छोटे शहरों में बसे वे करोड़ों लोग हैं, जो सीमित संसाधनों में भी अपने हुनर से रोजगार, उत्पादन और नवाचार की मिसाल पेश कर रहे हैं। इन्हीं लोगों के प्रयासों का संगठित स्वरूप है- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई। इसलिए बीते 11 साल में 'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस' के मूल मंत्र के साथ केंद्र सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए हैं, जिनके जरिए न सिर्फ ऋण और बाजार तक आसान पहुंच की सुविधा मिली है, बल्कि तकनीक के विस्तार सहित कारोबार में आसानी से लेकर नियमों के जाल से भी एमएसएमई को मुक्ति मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में एमएसएमई के लिए एक साथ 12 घोषणाएं करते समय कहा था, "जब बाधाएं टूटती हैं, तो फाइलों को भी गति मिल जाती है, अफसर खुद फाइलें लेकर, आगे बढ़कर फैसले सुनिश्चित कराने लगते हैं।"

आज 6.63 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई (जुलाई, 2025 तक) और बीते 5 वर्षों में ही करीब 29 करोड़ लोगों को रोजगार का रिकॉर्ड आंकड़ा यह बताने के लिए काफी है कि इन 7 वर्षों में केंद्र सरकार की पहलों का कितना असर इस सेक्टर पर हुआ है।

आसानी से मिले लोन... बना रहे कैश फ्लो

- **59 मिनट में लोन** : सैद्धांतिक मंजूरी के बाद **www.psbloansin59minutes.com** पोर्टल के माध्यम से 1 करोड़ रुपये तक के लोन स्वीकृत किए जाते हैं।

70,000 करोड़ रुपये से अधिक के 2.30 लाख लोन जारी।

500 करोड़ रुपये के कारोबार वाली सभी कंपनियों को अनिवार्य रूप से व्यापार प्राप्तियां ई-डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) में जोड़ने की शुरुआत।

- जीएसटी में पहले से पंजीकृत एमएसएमई को नए या अतिरिक्त लोन पर 2% कम ब्याज। प्री और पोस्ट शिपमेंट की अवधि के लोन पर लगने वाले ब्याज में 3% की बजाय 5% की छूट। लोन पर कम ब्याज की सुविधा 12 अगस्त 2021 तक, वहीं ब्याज में छूट की सुविधा जून 2024 तक जारी रही।

टेक्नोलॉजी अपग्रेड... | ताकि कम समय-खर्च में ज्यादा हो उत्पादन

- देश भर में इसके लिए 20 मुख्य केंद्र और टूल रूम के रूप में 100 सहायक केंद्र स्थापित करने की शुरुआत।
- 19 मुख्य केंद्रों के लिए अभी तक जमीन तय हो चुकी है। वहीं, 40 स्थानों पर सहायक केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी जा चुकी है। 23 में प्रशिक्षण और सहायता देने की शुरुआत भी हो चुकी है।

3,500 करोड़ रुपये के बजट वाली यह योजना वित्त वर्ष 2025-26 तक लागू करने की मंजूरी दी गई है।

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर हिस्सेदारी

- सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए कुल खरीद में 20% की बजाय 25% एमएसएमई से खरीदने की अनिवार्यता।

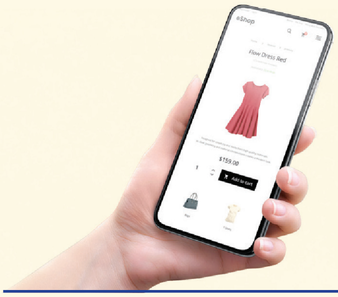

93,911

करोड़ रुपये की खरीद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने 2024-25 में एमएसएमई के जरिए की। यह कुल खरीद में करीब 40 फीसदी हिस्सेदारी है।

- एमएसएमई से अनिवार्य 25% खरीद में 3 फीसदी हिस्सेदारी महिला उद्यमियों के लिए आरक्षित।
- केंद्र सरकार के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अनिवार्य रूप से गवर्मेंट ईमार्केट-प्लेस (जेम) का हिस्सा बनाना।

45,000

महिला उद्यमियों के नेतृत्व वाली एमएसएमई से खरीद की गई वित्त वर्ष 2024-25 में।

39%

से अधिक हिस्सा है एमएसएमई का जेम पर कुल ऑर्डर में। 249 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अगस्त, 2024 तक जेएम पर जोड़ा जा चुका है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस...
ताकि कम हो सरकार का दखल

- 8 श्रम कानूनों और 10 केंद्रीय नियमों के अंतर्गत रिटर्न साल में केवल एक बार दायर करने की शुरुआत।
- फर्मों के निरीक्षण को अधिक पारदर्शी और आसान बनाने के लिए निरीक्षण, कंप्यूटर से रेंडम तय करने की शुरुआत।
- उद्यम लगाने के लिए पर्यावरण और स्थापना संबंधित मंजूरी। एक स्टेप में जल और वायु के प्रदूषण सहित पर्यावरण मंजूरी के निर्देश राज्यों को केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने 2 नवंबर 2018 को जारी किए। हालांकि, यह मामला अदालत में विचाराधीन है।
- कंपनी अधिनियम के तहत मामूली उल्लंघन के लिए उद्यमी को अब न्यायालय नहीं जाना पड़ेगा। इसके तहत 2 नवंबर, 2018 को अध्यादेश जारी हुआ। अब कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019 बन चुका है।

कर्मचारियों में हो सुरक्षा की भावना

- एमएसएमई क्षेत्र के कर्मी के पास जन धन खाता, भविष्य निधि और बीमा सुनिश्चित करने के लिए मिशन की शुरुआत। इसके तहत प्रधानमंत्री जन धन खाता में एमएसएमई कर्मचारियों को शामिल करने के अलावा भविष्य निधि और प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के साथ ही अटल पेंशन योजना को लेकर जागरूकता फैलाई गई।

एमएसएमई को बढ़ावा देने की दिशा में उठाए गए कदम

- एमएसएमई वर्गीकरण के लिए नए संशोधित मानदंड।
- कारोबार को सरल बनाने के लिए 'उद्यम पंजीकरण'।
- अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों के लिए उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म।
- खुदरा और थोक व्यापारियों को एमएसएमई के रूप में शामिल करना।
- 2 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त लोन सुविधा व रोजगार के अवसरों के लिए ऋण गारंटी योजना का संवर्धन। गारंटी सीमा 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये की गई।
- 18 व्यवसायों के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत।
- आत्मनिर्भर भारत निधि की स्थापना।
- समाधान पोर्टल की शुरुआत की गई, ताकि सूक्ष्म और लघु उद्यमों के भुगतान की निगरानी की जा सके।
- निर्यातक एमएसएमई के लिए 20 करोड़ रुपये तक के लोन के लिए गांरटी।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का भारत दौरा

मजबूत हो रही दो प्रमुख लोकतंत्र की साझेदारी

भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच साझेदारी की जीवंत कड़ी वहां बसे 18 लाख से अधिक भारतीय हैं जो दोनो देशों के बीच मित्रता, सहयोग व विकास के पुल को मजबूत कर रहे हैं। इसी साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीर स्टार्मर 8 अक्टूबर को भारत की दो दिवसीय यात्रा पर आए। भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए) के कुछ ही महीने बाद अब तक के सबसे बड़े बिजनेस डेलीगेशन के साथ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत-यूके साझेदारी में बनी नई ऊर्जा और व्यापक दृष्टि का प्रतीक...

भारत-यूके द्विपक्षीय वार्षिक व्यापार 56 अरब डॉलर का है जिसे 2030 तक बढ़ाकर दोगुना करने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट (सीईटीए) महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा जिससे आने वाले समय में व्यापार और निवेश के नए रास्ते खुलेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास जताया है कि यह लक्ष्य पहले ही हासिल कर सकते हैं। यही वजह है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की यह यात्रा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सर कीर स्टार्मर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात में दोनों देशों ने व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर सहमति जताई गई। संयुक्त बयान में, भारत और ब्रिटेन ने मिलकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) केंद्र, कनेक्टिविटी, इनोवेशन सेंटर और क्रिटिकल मिनरल्स इंडस्ट्री गिल्ड स्थापित करने का फैसला किया। इसके अलावा, रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ रिसर्च और क्लाइमेट टेक्नोलॉजी स्टार्टअप फंड में संयुक्त निवेश की घोषणा भी की गई। इन समझौतों से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को गति, यूके की 9 यूनिवर्सिटी के कैंपस का भारत में विस्तार और आधुनिक तकनीक के उपयोग से समान आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यात्रा के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीर स्टार्मर ने नौ अक्टूबर को मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में मुख्य भाषण दिया। दोनों नेताओं के बीच मुंबई में सीमित और

"आज ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल फाइनेंशियल इनोवेशन और फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का ग्लोबल प्लेटफॉर्म बन चुका है। इस बार इस फेस्टिवल में यूनाइटेड किंगडम एक पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल है। दुनिया की दो बड़ी डेमोक्रेसी के बीच यह पार्टनरशिप ग्लोबल फाइनेंशियल लैंडस्केप को और बेहतर बनाएगी।

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की यात्रा और ग्लोबल फिनटेक फेस्ट

- प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री स्टार्मर ने मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के छठे संस्करण में मुख्य संबोधन दिया।
- ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025, दुनिया भर के नवप्रवर्तकों, नीति निर्माताओं, केंद्रीय बैंकरों, नियामकों, निवेशकों, शिक्षाविदों और उद्योग जगत के प्रमुख एक साथ एक मंच पर आए।
- सम्मेलन का मुख्य विषय, 'एक बेहतर विश्व के लिए वित्त का सशक्तीकरण' था। यह एआई, संवर्धित बुद्धिमत्ता, नवाचार और समावेशन विषय के इर्द-गिर्द रहा।
- इस आयोजन में लगभग 7,500 कंपनियां, 800 वक्ता, 400 प्रदर्शक और भारतीय तथा अंतरराष्ट्रीय क्षेत्राधिकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले 70 विनियामक ने भाग लिया।

75
से अधिक देशों के एक लाख से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया कार्यक्रम में।

पहली बार भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टार्मर

- ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीर स्टार्मर 8-9 अक्टूबर 2025 को भारत के दौरे पर रहे। यह प्रधानमंत्री स्टार्मर की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा थी।
- इस यात्रा के दौरान, दोनों प्रधानमंत्री ने 'विजन 2035' के अनुरूप भारत-ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं में प्रगति की समीक्षा की।
- यह विजन व्यापार-निवेश, प्रौद्योगिकी-नवाचार, रक्षा-सुरक्षा, जलवायु-ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों के प्रमुख स्तंभों में कार्यक्रमों व पहलों का एक केंद्रित और समयबद्ध दस वर्षीय रोडमैप है।
- दोनों नेताओं ने भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते द्वारा प्रस्तुत अवसरों पर व्यवसायों एवं उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ चर्चा की। यह भविष्य की भारत-ब्रिटेन आर्थिक साझेदारी का एक केंद्रीय स्तंभ है।
- क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। दोनों नेताओं ने उद्योग विशेषज्ञ, नीति निर्माता और नवप्रवर्तकों के साथ भी वार्तालाप किया।

पीएम मोदी ने रखे 4 नए आयाम

कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट (सीईटीए) अपनी पूरी संभावना को प्राप्त कर सके, इसके लिए पीएम मोदी ने यूके सीईओ फोरम के समक्ष चार नए आयाम रखे। उन्होंने कहा कि यह नए आयाम शायद इसको काफी ब्रॉड बेस देंगे।

C, यानी कॉमर्स एंड इकोनॉमी

E, यानी एजुकेशन एंड पीपुल-टू-पीपुल टाई

T, यानी टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन

A, यानी एस्पिरेशन

प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी हुई।

मौजूदा वैश्विक अस्थिरता के दौर में, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच बढ़ती हुई साझेदारी वैश्विक स्थिरता और आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण आधार बनी रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त प्रेस वक्तव्य में पीएम मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री स्टार्मर के नेतृत्व में, भारत और ब्रिटेन के रिश्तों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस साल जुलाई में मेरी ब्रिटेन यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक सीईटीए पर सहमति बनाई गई थी। इससे दोनों देशों की इम्पोर्ट लागत में कमी आएगी तो वहीं युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर और व्यापार-उद्योग में मदद मिलेगी। बैठक में दोनों नेताओं ने इंडो-पेसिफिक, पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता और यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर भी विचार साझा किए गए। पीएम मोदी ने अपने वक्तव्य में कहा कि यूक्रेन विवाद और गाजा के मुद्दे पर भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी से शांति की बहाली के सभी प्रयासों का समर्थन करता है। हम भारत-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं।■

प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

अन्नदाता को धन धान्य व दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की सौगात

बीते 11 वर्षों से केंद्र सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि किसान सशक्त हों और कृषि पर ज्यादा निवेश हो। करीब 6 गुना बजट, ढाई गुना से ज्यादा उर्वरक सब्सिडी और फसल की बुवाई के पहले से लेकर बाजार तक साथ वाली क्रांतिकारी योजनाएं अन्नदाताओं के प्रति केंद्र सरकार की इसी प्रतिबद्धता का उदाहरण बनी हैं। इस बार 11 अक्टूबर को किसानों को प्राथमिकता की साक्षी बनी राजधानी नई दिल्ली, जब कृषि धन धान्य योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीं 41 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की सौगातें...

भारत की विकास यात्रा में खेती और किसानी हमेशा से एक प्रमुख हिस्सा रही है। बहुत जरूरी होता है कि बदलते समय के साथ खेती किसानी को सरकार का सहयोग मिलता रहे। इसके लिए वर्तमान केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने से लेकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है। दरअसल 2014 के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी विजन के साथ केंद्र सरकार ने किसानों के हित में, बीज से लेकर बाजार तक अनगिनत रिफॉर्म किए।

दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान देश के अन्नदाताओं की विकास यात्रा पर बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन रिफॉर्म के साथ नई शुरुआत और उनसे मिले परिणामों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बीते

धन धान्य योजना के साथ खेती में सबसे ज्यादा पिछड़े जिलों पर फोकस

- पीएम धन-धान्य कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य देश के हर खेत तक सिंचाई सुविधा पहुंचाना, फसल उत्पादकता बढ़ाना, किसानों को आसान ऋण और भंडारण सुविधा प्रदान करने के साथ नई कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- 6 वर्षों के लिए 24,000 करोड़ रुपये की लागत वाली योजना के तहत चयनित जिलों में कृषि ढांचे के विकास, जल प्रबंधन और फसल विविधता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आकांक्षी जिला अभियान की तर्ज पर शुरू इस योजना का लाभ करीब 1.7 करोड़ किसानों को होगा।
- सरकार ने ऐसे 100 पिछड़े जिलों को चुना है, जहां 11 विभागों की 36 योजनाएं मिलकर काम करेंगी।

11 वर्षों में भारत का कृषि निर्यात करीब-करीब दो गुना हो गया, अनाज उत्पादन करीब 900 लाख मीट्रिक टन और बढ़ गया, फल व सब्जियों का उत्पादन 640 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा बढ़ गया। भारत आज दूध उत्पादन में दुनिया में नंबर एक तो मछली उत्पादन में नंबर 2 पर है। यही नहीं, 2014 की तुलना में शहद और अंडे का उत्पादन दोगुना हो गया है। इस दौरान देश में 6 बड़ी फर्टिलाइजर फैक्ट्री शुरू की गईं। 25 करोड़ से ज्यादा मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को मिले हैं, 100 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि तक सूक्ष्म सिंचाई की सुविधा पहुंची है, पीएम फसल बीमा योजना से करीब दो लाख करोड़ रुपये क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं। 10 हजार से ज्यादा किसान उत्पाद संघ (एफपीओ) बने हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 3 लाख 75 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में भेजे जा चुके हैं।

धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश का स्वभाव ऐसा बन गया है कि वो कुछ उपलब्धियों से ही संतुष्ट नहीं होता है। देश के 100 जिलों को पिछड़ा घोषित कर छोड़ दिया गया था। इनमें 20 प्रतिशत बस्तियां ऐसी थीं, जिन्होंने आजादी के बाद से सड़क ही नहीं देखी थी। यहां 17 प्रतिशत बच्चे टीकाकरण के दायरे से बाहर थे। 15% स्कूलों में बिजली नहीं थी लेकिन, वर्तमान केंद्र सरकार ने इन्हें पिछड़े की बजाय आकांक्षी जिला घोषित कर विशेष फोकस किया। प्राथमिकता मिली तो यह जिले अब कई पैरामीटर पर अन्य जिलों के मुकाबले बेहतर परिणाम लाने में सफल रहे। पीएम धन धान्य कृषि योजना इसी मॉडल पर तैयार की गई है। इस योजना के लिए 100 जिलों का चयन तीन पैरामीटर पर किया गया है। पहला-खेत से कितनी पैदावार होती है। दूसरा- एक खेत में कितनी बार खेती होती है और तीसरा- किसानों को लोन या निवेश की कोई सुविधा है? और है तो कितनी मात्रा में है?

दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये सिर्फ दाल उत्पादन बढ़ाने का मिशन नहीं है, बल्कि हमारी भावी पीढ़ी को सशक्त बनाने का भी अभियान है। उन्होंने कहा कि पोषण की दिशा में दलहन प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। लेकिन, भारत के लिए यह बड़ी चुनौती है कि कृषि प्रधान देश होने के बावजूद वह आज भी बड़ी मात्रा में दाल का आयात करता है। यह मिशन इसी क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की एक शुरुआत है। इसका लक्ष्य है दाल की खेती में 35 लाख हेक्टेयर की वृद्धि करना।

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दलहन की खेती में लगे किसानों से बातचीत की, जिन्हें कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन में मूल्य-श्रृंखला आधारित दृष्टिकोण स्थापित करने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। इन किसानों को किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की

दलहन आत्मनिर्भरता मिशन से 2 करोड़ से ज्यादा किसानों को लाभ

- यह मिशन पोषण सुरक्षा और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसका उद्देश्य दलहन उत्पादकता के स्तर में सुधार, दलहन की खेती के रकबे का विस्तार, मूल्य श्रृंखला - खरीद, भंडारण, प्रसंस्करण को मजबूत करना और नुकसान को कम करना है।
- दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता मिशन की घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई थी और 1 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसे मंजूरी दी गई। 11,440 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ इसे 2025-26 से 2030-31 के दौरान क्रियान्वित किया जाएगा।
- मिशन के अंतर्गत 2030-31 तक दाल उत्पादन को 350 लाख टन, दलहन क्षेत्रफल को 310 लाख हेक्टेयर पहुंचाने का लक्ष्य है। इसमें विशेष रूप से तुअर (अरहर), उड़द और मसूर पर ध्यान केंद्रित किया गया है। किसानों से एमएसपी पर इनकी 100 फीसदी खरीद की जाएगी।
- मिशन के तहत कटाई से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए 1,000 इकाइयों की स्थापना की जाएगी। प्रसंस्करण और पैकेजिंग इकाइयों की स्थापना के लिए अधिकतम 25 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी।
- नई किस्मों के बीजों तक किसानों की आसान पहुंच के लिए 88 लाख मुफ्त बीज किट वितरित की जाएंगी। यही नहीं, वर्ष 2030-31 तक 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज दलहन उत्पादक किसानों को दिए जाएंगे। इस मिशन का लाभ करीब 2 करोड़ किसानों को होगा।
- दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता। दालों के उत्पादन में भारत ने बीते 11 सालों में करीब 31 फीसदी की बढ़ोतरी की है। इसके बाद भी अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए वर्ष 2023-24 में भारत ने 47.38 लाख टन दालों का आयात किया, जबकि इसके मुकाबले निर्यात केवल 5.94 लाख टन रहा। आत्मनिर्भरता के साथ निर्यात में बढ़ोतरी की दिशा में दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की गई।

6 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास

- प्रधानमंत्री ने कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में 5,450 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जबकि लगभग 815 करोड़ रुपये की अतिरिक्त परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया।
- बेंगलुरु और जम्मू-कश्मीर में कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र, अमरेली और बनास में उत्कृष्टता केंद्र, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत असम में कृत्रिम गर्भाधान प्रयोगशाला की स्थापना, मेहसाणा, इंदौर व भीलवाड़ा में दूध पाउडर संयंत्र, असम के तेजपुर में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मछली चारा संयंत्र, कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए बुनियादी ढांचा, एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्यवर्धन बुनियादी ढांचा का उद्घाटन किया गया।
- जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई, उनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णा में एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्यवर्धन बुनियादी ढांचा (विकिरण) के साथ ओडिशा के हीराकुंड में अत्याधुनिक एकीकृत एक्वा पार्क शामिल है।

सदस्यता और कृषि अवसंरचना कोष के तहत सहायता भी मिली है।

वर्ष 2047 में विकसित राष्ट्र का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे भारत के लिए यह समय दो तरफा प्रयासों का है। देश को एक तरफ आत्मनिर्भर होना है तो दूसरी तरफ वैश्विक बाजार में अपनी भूमिका को सशक्त कर दुनिया के दरवाजों पर दस्तक देनी है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन खाद्य क्षेत्र में भारत के इसी संकल्प को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।■

Narendra Modi
@narendramodi

अपने किसान भाई-बहनों से संवाद के दौरान यह जानकर बेहद खुशी हुई कि वे देश को कृषि और दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बढ़-चढ़कर भागीदारी करना चाहते हैं।

Rajnath Singh
@rajnathsingh

पिछले दस वर्षों में भारत का रक्षा उत्पादन ₹46,425 करोड़ से बढ़कर ₹1.5 लाख करोड़ के ऐतिहासिक स्तर पर पहुँच गया है। इसमें ₹33,000 करोड़ का योगदान निजी क्षेत्र से आना दर्शाता है कि आत्मनिर्भर भारत की रक्षा यात्रा अब एक राष्ट्रीय आंदोलन बन चुकी है।

Amit Shah
@AmitShah

भारत का पहला सहकारी कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र प्रतिदिन 12 टन CBG का उत्पादन और 75 टन पोटाश का निर्माण करेगा, जिससे इन दोनों उत्पादों का विदेशों से आयात कम होगा।

Office Of Nitin Gadkari
@OfficeOfNG

Puducherry is taking a big step forward in its National Highway network, marking a new chapter of growth and prosperity.

Union Minister Shri @nitin_gadkari Ji will lay the foundation stone and dedicate to the nation 3 National Highway projects worth over ₹2,000 crore in Puducherry on Monday, 13th October 2025, at 11:00 AM, at the Agriculture Complex Ground, Thattanchavady, Puducherry.

Piyush Goyal
@PiyushGoyal

Marking 4 years of #PMGatiShakti, a game-changing initiative by PM @NarendraModi ji, which has transformed India's infrastructure planning through a 'Whole-of-Government' approach.

By integrating Ministries, States/UTs & sectors on one digital platform, it has brought speed, synergy & sustainability to project execution.

Driving seamless connectivity and logistics efficiency, PM GatiShakti stands as a cornerstone in our journey towards a Viksit Bharat. 🇮🇳

Dharmendra Pradhan
@dpradhanbjp

किसान सशक्तीकरण का नया अध्याय!

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार का कृषि और किसान उत्थान के प्रति समर्पण आज नया आयाम स्थापित करने जा रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी 'पीएम धन-धान्य कृषि योजना' और 'दलहन आत्मनिर्भरता मिशन' का शुभारंभ करेंगे। 42,000 करोड़ रुपये से अधिक की इन परियोजनाओं से कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा मिलेगी और किसानों के जीवन में खुशहाली के नए द्वार खुलेंगे।

आत्मनिर्भर होने के साथ वैश्विक बाजार के लिए भी उत्पादन करें किसान : मोदी

प्रधानमंत्री का दिवाली से पहले 35,440 करोड़ की धन-धान्य योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का तोहफा

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत बनाने में किसानों की बहुत बड़ी भूमिका है। अब हमें आत्मनिर्भर बनने के साथ वैश्विक बाजार के लिए भी उत्पादन करना है। हमें दुनिया के दरवाजों पर दस्तक देनी है। ऐसी फसलों पर जोर देना है, जो दुनिया की मंडियों में छा जाएं। उन्होंने कहा, आजादी के बाद किसानों ने ही देश को अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया है।

पीएम मोदी ने दिवाली से पहले देशभर के किसानों को 35,440 करोड़ रुपये की दो बड़ी योजनाओं प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का तोहफा दिया। पीएम मोदी ने कहा, दोनों योजनाएं करोड़ों किसानों का भाग्य बदलने का काम करेंगी।

पीएम मोदी ने शनिवार को पूसा परिसर में इन योजनाओं के आगाज के साथ, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में 5,450 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। करीब 815 करोड़ रुपये की अतिरिक्त परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने कहा, 24,000 करोड़ रुपये की धन धान्य कृषि योजना और 11,440 करोड़ रुपये का दलहन आत्मनिर्भरता मिशन किसानों का भाग्य बदल देगा। उन्होंने कहा, देश का मिजाज ऐसा बन गया है कि वह कुछ उपलब्धियों से ही संतुष्ट नहीं होता। हमें विकसित बनना है, तो हर क्षेत्र में लगातार बेहतर करते ही रहना होगा, सुधार करना ही होगा। धन-धान्य योजना की प्रेरणा आकांक्षी जिला योजना की सफलता है। उन्होंने कहा, पहले की सरकारें देश के सौ से अधिक जिलों को पिछड़ा घोषित कर भूल गई थीं लेकिन हमने उन जिलों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। इसी मॉडल पर हम खेती में पिछड़े 100 जिलों पर ध्यान केंद्रित कर काम करना चाहते हैं।

दिल्ली स्थित पूसा संस्थान में शनिवार को किसानों से बातचीत करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एजेंसी

36 योजनाओं को जोड़ा...पीएम मोदी ने कहा, धन-धान्य योजना में 36 योजनाएं एकसाथ जोड़ी हैं-जैसे प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन, सिंचाई के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप, तेल उत्पादन के लिए तिलहन मिशन है। इस योजना में पशुधन पर भी विशेष फोकस किया जा रहा है। इसमें किसानों के साथ सरकारी कर्मचारियों और जिले के डीएम पर बड़ी जिम्मेदारी है। विश्वास है, युवा साथी किसानों के साथ सौ जिलों की खेती की तस्वीर बदल देंगे। इससे पूरे गांव की आर्थिकी बदल जाएगी।

बीज से बाजार तक व्यापक सुधार

तेजी से विकसित हो रहे 21वीं सदी के भारत को मजबूत और सुधरी हुई कृषि प्रणाली की जरूरत है। यह बदलाव 2014 के बाद हमारी सरकार के आने के बाद शुरू हुआ। हमने अतीत की उदासीनता को तोड़ा। बीज से बाजार तक, किसानों के हित में व्यापक सुधार लागू किए। सुधार सिर्फ नीतिगत बदलाव नहीं थे, संरचनात्मक हस्तक्षेप थे, जिनका मकसद भारतीय कृषि को आधुनिक, टिकाऊ और सुगम बनाना था। -नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

यह मेरे लिए गर्व का क्षण

पीएम मोदी ने कहा, किसान, पशुपालक और मछुआरा भाई-बहनों के कल्याण के लिए हम दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। इसी दिशा में हजारों करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन-शिलान्यास मेरे लिए गर्व का क्षण है।

भावी पीढ़ी को सशक्त बनाने का मिशन

पीएम मोदी ने कहा कि दलहन आत्मनिर्भरता मिशन सिर्फ दाल उत्पादन बढ़ाने का मिशन नहीं है, बल्कि भावी पीढ़ी को सशक्त बनाने का भी अभियान है। भारत के किसानों ने रिकॉर्ड अनाज उत्पादन किया है। गेहूं हो या धान, आज भारत दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। हमें आटे-चावल से भी आगे बढ़कर सोचना ही होगा।

- पीएम कहा कि हम कृषि प्रधान देश तो हैं, लेकिन दुर्भाग्य देखिए आज भी देश बड़ी मात्रा में दाल का आयात करता है। इसलिए दलहन आत्मनिर्भरता मिशन बहुत जरूरी है। पीएम ने 2030 तक दलहन की खेती का रकबा 35 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाने का आग्रह किया।
- पीएम ने कहा, दलहन मिशन का लक्ष्य 2030-31 तक दलहन उत्पादन को मौजूदा 252.38 लाख टन से बढ़ाकर 350 लाख टन करना है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा : मोदी

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर (ब्यूरो)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि विशाखापत्तनम में गूगल कृत्रिम मेधा केंद्र की स्थापना प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण में एक बेहद महत्त्वपूर्ण कदम होगा।

मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, 'आंध्र प्रदेश के शहर विशाखापत्तनम में गूगल कृत्रिम मेधा केंद्र की स्थापना को लेकर काफी खुश हूं।' प्रधानमंत्री ने लिखा कि बहुआयामी निवेश जिसमें गीगावाट पैमाने पर डेटा केंद्र अवसंरचना शामिल है... यह सरकार के 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण के अनुरूप है। मोदी ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के एक 'पोस्ट' पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, 'यह प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण में एक बेहद महत्त्वपूर्ण कदम होगा। यह सभी के लिए एआइ सुनिश्चित करेगा, हमारे नागरिकों को अत्याधुनिक उपकरण प्रदान करेगा, हमारी डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा।

आतंकी अगर पाताल में भी छिपे होंगे तो निकालकर देंगे दंड : शाह

शाह ने 141 करोड़ की लागत से मानेसर में एनएसजी के ट्रेनिंग सेंटर का किया शिलान्यास

अमर उजाला ब्यूरो

मानेसर (हरियाणा)। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकवादी कहीं भी छिपे होंगे, भारतीय सेना उन्हें पाताल से भी निकालकर दंड देगी। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर शाह ने कहा कि जहां आतंकवादी हमलों की योजना बनती थी और जहां प्रशिक्षण दिया जाता था, उन स्थानों को ध्वस्त कर हमने साबित किया कि आतंकवादियों को दुनिया में कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिल सकती।

शाह एनएसजी के 41वें स्थापना दिवस समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने यहां 141 करोड़ रुपए की लागत से 8 एकड़ भूमि पर एनएसजी के स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर (एसओटीसी) का शिलान्यास भी किया। उन्होंने बताया कि इस केंद्र में अत्याधुनिक तरीके से आतंकवाद से निपटने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि इस केंद्र पर एनएसजी के अलावा देश भर की राज्य पुलिस के आतंकरोधी दस्तों का प्रशिक्षण भी होगा। उन्होंने कहा कि इतने विशाल देश में आतंकवाद का सामना करने के लिए केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों के सहयोग की भी जरूरत है।

एनएसजी ने देशभर के 770 संवेदनशील स्थानों का डाटा बैंक किया तैयार...शाह ने बताया कि एनएसजी ने देश भर के कुल 770 महत्वपूर्ण स्थानों की रैकी कर अचानक होने वाले आतंकी हमलों से बचाव के लिए डाटा बैंक तैयार किया है। इन स्थानों में कई अस्पताल, धार्मिक स्थान, जलमार्ग और संसद जैसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान शामिल हैं। शाह ने कहा कि सरकार की योजना आने वाले वक्त में एनएसजी को अत्याधुनिक तकनीक से लैस करने की है।

एनएसजी के 41वें स्थापना दिवस पर मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में एसओटीसी का शिलान्यास करने जाते हुए गृह मंत्री अमित शाह।

आतंकवाद के खिलाफ जारी रहेगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति

शाह ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी। नीति का उल्लेख करते हुए उन्होंने ने कहा कि 2019 के बाद से ही इसके लिए लगातार कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने यूएपीए और एनआईए अधिनियम में संशोधन किया। साथ ही आतंकी समूहों की फंडिंग की वैज्ञानिक जांच प्रणाली बनाकर इस पर प्रवर्तन निदेशालय को सक्रिय किया। पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया।

- मल्टी एजेंसी सेंटर (मैक) को मजबूत किया। साथ ही उन कानूनी कमियों को दूर किया है जिनके सहारे आतंकी अदालतों से बच निकलते थे। 57 से अधिक व्यक्तियों या संस्थाओं की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है।

अयोध्या में स्थापित होगा ब्लैक कैट कमांडो बल का नया हब

शाह ने कार्यक्रम में घोषणा की कि सरकार उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 'ब्लैक कैट' कमांडो बल नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (एनएसजी) का एक नया क्षेत्रीय हब स्थापित करेगी। यह देश में एनएसजी का छठा हब होगा।

- अब तक एनएसजी के हब मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और गांधीनगर में हैं, जबकि जम्मू में इसका एक छोटा 'टास्क फोर्स' यूनिट कार्यरत है। एनएसजी के इन हबों का उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में किसी भी आपात स्थिति या आतंकवादी हमले की स्थिति में कमांडो को तुरंत और प्रभावी ढंग से तैनात करना है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आने वाले दिनों में एनएसजी के कामकाज में व्यापक सुधार लाने जा रही है।

1984 में हुई स्थापना, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ 'जीरो एरर' फोर्स

एनएसजी देश की विशेष आतंकवाद-रोधी बल है, जो लंबी और जटिल अभियानों में सहायता प्रदान करती है। 1984 में गठित एनएसजी को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ 'जीरो एरर' फोर्स माना जाता है। यह आतंकवादी हमलों, विमान अपहरण जैसे खतरों का तुरंत जवाब देने और वीआईपी सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है।

पीएम मोदी ने क्वालकॉम के सीईओ के साथ भारत की प्रगति पर की चर्चा

एआई, सेमीकंडक्टर मिशन और 6जी क्षेत्र में सहयोग करेगी

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका स्थित चिप दिग्गज क्वालकॉम के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) क्रिस्टियानो आर. अमोन से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनोवेशन और कौशल में भारत की प्रगति पर चर्चा की। पीएम मोदी ने भारत के सेमीकंडक्टर और एआई मिशनों के प्रति क्वालकॉम की प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत ऐसी तकनीकों के निर्माण के लिए खास प्रतिभा और पैमाने प्रदान करता है।

कंपनी एआई स्मार्टफोन, पीसी, स्मार्ट ग्लास विकसित करेगी
ऑटो, इंडस्ट्रियल और अन्य क्षेत्रों में भी अपनी सेवाएं देगी

भारत के डिजिटल भविष्य में अग्रणी भूमिका

इससे पहले क्वालकॉम इंडिया ने बताया कि कंपनी भारत के डिजिटल भविष्य को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभा रही है। साथ ही, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी तकनीकी समाधानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दे रही है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) 2025 में क्वालकॉम ने एज एआई और 6जी से लेकर स्मार्ट होम, कनेक्टेड डिवाइस और एडवांस कंप्यूट प्लेटफॉर्म तक अलग-अलग तरह के इनोवेशन को पेश किया। साथ ही बताया गया कि कंपनी की तकनीकें भारत के डिजिटल परिवर्तन को किस प्रकार गति देने का काम करेंगी।

नवाचार और कौशल की प्रगति पर की चर्चा

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर क्रिस्टियानो के एक पोस्ट को रिपोस्ट कर लिखा कि क्रिस्टियानो आर। अमोन से मुलाकात बेहद खास औप्र अच्छी रही। हमने एआई, इनोवेशन और स्किल को लेकर भारत की प्रगति पर चर्चा की। भारत के सेमीकंडक्टर और एआई मिशनों को लेकर क्वालकॉम की प्रतिबद्धता को देखकर खुशी हुई। देश ऐसी तकनीकों के निर्माण के लिए अनमैच्ड टैलेंट और पैमाने प्रदान करता है।

मंगोलिया के नागरिकों को मुफ्त ई-वीजा देगा भारत : पीएम मोदी

प्रधानमंत्री की मंगोलियाई राष्ट्रपति हुरेलसुख के साथ वार्ता, कहा-विकास साझेदारी में भारत भरोसेमंद साथी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगोलियाई राष्ट्रपति हुरेलसुख उखना के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान कहा कि मंगोलिया के विकास में भारत भरोसेमंद सहयोगी रहा है और दोनों देश एक स्वतंत्र, खुले और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करते हैं। उन्होंने मंगोलियाई नागरिकों के लिए मुफ्त ई-वीजा देने और उसके सीमा सुरक्षाबलों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू करने की भी घोषणा की। दोनों देशों ने सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने के लिए करार पर हस्ताक्षर भी किए।

[illegible]

नई दिल्ली में मंगलवार को पीएम मोदी से मिले मंगोलियाई राष्ट्रपति हुरेलसुख उखना।

नई दिल्ली, अमृतसर के लिए सीधी उड़ान सेवा

[illegible]

रक्षा मंत्री राजनाथ के साथ राष्ट्रपति उखना।

वासुदेव बलवंत फड़के
4 नवंबर 179वीं जयंती

भारतीय सशस्त्र विद्रोह के जनक को राष्ट्र का शत शत नमन

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सशस्त्र क्रांति की नींव रखने वाले आदि क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के ने देशवासियों को जाति, धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठने और संगठित होकर अंग्रेजों के खिलाफ मुक्ति संग्राम के लिए प्रेरित किया। अपने शौर्य, पराक्रम व सूझबूझ से ब्रिटिश शासन को भयभीत कर फड़के भावी क्रांतिकारियों के लिए मार्गदर्शक बने। मां भारती की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान करने वाले इस भारतीय सशस्त्र विद्रोह के जनक का जीवन राष्ट्रवासियों को युगों-युगों तक करता रहेगा प्रेरित...

जन्म : 4 नवंबर 1845
मृत्यु : 17 फरवरी 1883

14 जून 2022 को मुंबई स्थित राजभवन में जल भूषण भवन और क्रांतिकारियों की गैलरी के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वासुदेव बलवंत फड़के को याद करते हुए कहा था कि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर सशस्त्र क्रांति का रास्ता अपनाया। क्रांतिकारियों की यह गैलरी वासुदेव बलवंत फड़के, चापेकर बंधुओं, सावरकर भाइयों, मैडम भीकाजी कामा, वी बी गोगेट, 1946 के नौसेना विद्रोह के नायकों सहित अन्य लोगों के योगदान को श्रद्धांजलि देती है।

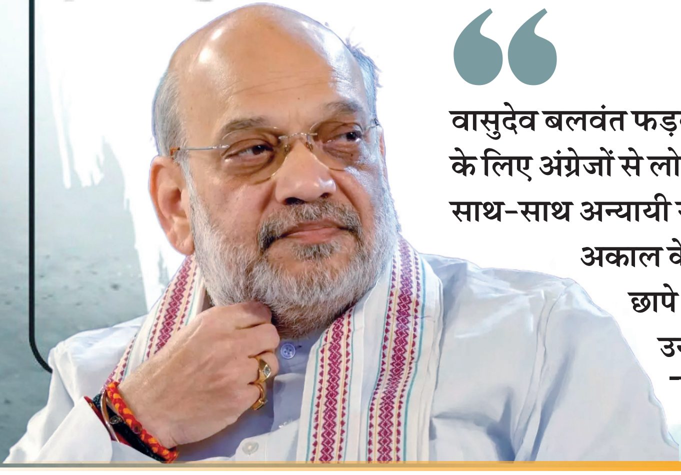

वासुदेव बलवंत फड़के एक ऐसे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया। 19वीं सदी की शुरुआत से ही उनके नाम से अंग्रेजों के साथ-साथ अन्यायी साहूकारों के मन में डर था। एक अग्रणी क्रांतिकारी के रूप में, उन्होंने अकाल के दौरान गरीबों की गाढ़ी कमाई हड़पने वाले साहूकारों के घरों पर छापे मारे और मिली रकम का इस्तेमाल सशस्त्र क्रांति के लिए किया। मैं उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

– **अमित शाह**, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

न्यू इंडिया समाचार पाक्षिक

आर.एन.आई, DELHIN/2020/78812, 1-15 नवंबर, 2025

आरएनआई DELHIN/2020/78812, दिल्ली पोस्टल लाइसेंस नंबर- DL (S)-1/3550/2023-25 डब्ल्यूपीपी संख्या- U (S)-98/2023-25, posting at BPC, Market Road, New Delhi - 110001 on 26-30 advance Fortnightly (प्रकाशन तिथि- 16 अक्टूबर 2025, कुल पृष्ठ-44)

प्रधान संपादक: धीरेन्द्र ओझा, प्रधान महानिदेशक, पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

प्रकाशक और मुद्रक: कंचन प्रसाद, महानिदेशक, केंद्रीय संचार ब्यूरो

कमरा संख्या-278, केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना भवन, द्वितीय तल, नई दिल्ली- 110003 से प्रकाशित

मुद्रणः जेके ऑफसेट ग्राफिक्स प्रा. लि., बी-278, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110020